ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज

सच्ची खबर सबसे पहले

online- jwalaexpress.com

आर.एन.आई. नं. :- CHHHIN/2021/82386

वर्ष - 05, अंक -46 | दुर्ग (छ.ग.), दिनांक 16 जुलाई से 22 जुलाई (प्रत्येक गुरूवार) | पृष्ठ - 8, मूल्य - 05 रुपए

संक्षिप्त समाचार

बिहार के मुंगेर में बेटी के अपहरण का केस नहीं लिया वापस, अपहणकर्ताओं ने गोली मारी

पटना। बिहार के मुंगेर जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद है। अपराधियों ने पहले एक युवकी का अपहरण किया और जब युवती के पिता ने मामले की शिकायत पुलिस में दी तो उनकी हत्या कर दी गई। घटना फियासराय थाना क्षेत्र की है। यहां के डकरा सतखजुरिया गांव स्थित एक ईंट-भट्ठे पर 45 वर्षीय सुबोध कुमार यादव बुधवार रात को ड्यूटी कर रहे थे। तभी कुछ लोग आए और उनके सिर पर गोली मारकर फरार हो गए। सुबोध यादव की नाबालिग बेटी का मई में गायब हो गई थी। इसके बाद उन्होंने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। कुछ लोगों का कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का था, जबकि सुबोध ने इसे अपहरण का मामला बताकर नामजद शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी का परिवार सुबोध से नाराज था और बदला लेने की सोच रहा था।

गुजरात में तीन मिनट में दो बार आया भूकंप

अहमदाबाद। गुजरात के कच्छ जिले में तीन मिनट के अंतराल पर दो बार भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र कच्छ जिले में धोलावीरा से 32 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में स्थित था. रिक्टर पैमाने पर पहले आए भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई जबकि दूसरा झटका 3.2 की तीव्रता का रहा. हालांकि दोनों भूकंप की तीव्रता अधिक नहीं थी लेकिन लोगों ने कंपन को महसूस किया. पहला भूकंप दोपहर 2:20 बजे दर्ज किया गया. इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई. भूकंप का केंद्र खावड़ा से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित था. झटके हल्के थे, लेकिन कई इलाकों में लोगों ने कंपन महसूस किया. कुछ लोग एहतियात के तौर पर घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए. पहले झटके के ठीक तीन मिनट बाद, 2:23 बजे दूसरा भूकंप आया.

कांग्रेस राम मंदिर, पेपर लीक और एथनॉल के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी

नई दिल्ली। कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वह संसद के आगामी मानसून सत्र में केंद्र सरकार को शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी अनियमितता, पेपर लीक, राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी, एथनॉल, परिसीमन से जुड़े विषय तथा कई अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगी. पार्टी का यह भी कहना है कि वह इस सत्र में विदेश नीति के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े विषय को भी प्रमुखता से उठाएगी. इसी क्रम में पार्टी की संसदीय रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10, जनपथ पर एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव के. सी. वेणुगोपाल, राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे.

विधानसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव

डॉ. महंत ने गिनाई सरकार की विफलताएं विधायक अजय चंद्राकर के तीखे बोल...

रायपुर। संवाददाता

विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने 136 बिंदुओं वाला अविश्वास प्रस्ताव सामने रखते हुए जमकर विष्णुदेव साय सरकार की विफ्लताएं गिनाई। वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर तीखे बोल बोले। डॉ. महंत व चंद्राकर ने एक-दूसरे की नाकामी के कई उदाहरण गिनाए। अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात शुरु करते हुए डॉ. महंत ने कहा कि विष्णु देव साय सरकार को 136 हफ्ते हो गए। हम 136 बिन्दुओं वाला आरोप पत्र लेकर आए हैं। डॉ. महंत ने अविभाजित मध्यप्रदेश के समय के पूर्व मंत्री संत कवि पवन दीवान की कविता का अपने भाषण में उल्लेख किया-

चुप-चुप रहकर
सब कुछ सहकर
सबका मान बढ़ाते हैं
बार-बार अपमानित होकर
गैरों का गुणगान कराते हैं
मेहमानों को खूब खिलाकर
चुपचाप सो जाते हैं
इसलिए ही छत्तीसगढ़िया
परबुद्धि कहलाते हैं
छत्तीसगढ़ में सब कुछ है
लेकिन कमी है स्वाभिमान की
मुझसे सही नहीं जाती
ऐसी चुप्पी वर्तमान की...

कविता की परबुद्धि वाली लाइन का डॉ. महंत व्दारा उल्लेख किये जाने पर वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी एवं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आपत्ति जताई और कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ऐसी राय कायम नहीं की जाती। डॉ. महंत ने कहा ये मेरा लिखा नहीं है। ये संत पवन दीवान की कविता है। डॉ. महंत ने मंत्री ओ.पी. चौधरी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि आप कब पैदा हुए यह मुझे मालूम न, लेकिन यह सच है कि 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया' नारा मेरे पिता का दिया हुआ है। हम छत्तीसगढ़ की मूल भावना को सामने रखे रहे हैं तो दूसरों को क्यों पीड़ा हो रही है। डॉ. महंत ने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव किसान, महिलाओं, युवाओं के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र का दस्तावेज है। 1963 में आचार्य जे.पी. कृपलानी ने नेहरू सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास पेश किया था। तब खुद नेहरू जी ने उसका स्वागत करते हुए कहा था कि सरकार के ख़िलाफ़ लोकतंत्र में ऐसी स्वस्थ बहस होती रहनी चाहिए। ये अच्छी परम्परा है। 1979 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ये महसूस हुआ कि सदन में उनकी पहले जैसी स्थिति नहीं रही, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही इस्तीफा देना स्वीकार कर लिया। डॉ. महंत ने कहा कि 26 जुलाई 2022 को हम लोगों ने एक अहम् निर्णय लिया था। सर्वसम्मति से एक संकल्प लाया था कि हसदेव में आबंटित कोल ब्लॉक को रद्द करते हैं। इस सरकार के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की शपथ भी नहीं हुई थी कि उससे पहले हसदेव अरण्य को काटने का सिलसिला शुरू हो गया। हसदेव अरण्य को मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। यह वहां के आदिवासियों की आस्था का प्रतीक है। मंत्रि मंडल के अस्तित्व में आने से पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों ने हसदेव को ब्लॉक को खनन के लिए सौंप दिया। पंद्रह हज़ार पेड़ों की कटाई शुरु हो गई। जिस रास्ते से भगवान राम गुजरे उसे उद्योगपति को सौंप दिया गया और हमारे हिस्से में क्या आया हाथी-मानव संघर्ष। डॉ. महंत ने कहा कि कोरिया जिले में 29 वर्षीय महिला का बलात्कार कर उसे ज़िंदा जला दिया गया। अपनी बात रखने थाने पहुंचे एक व्यक्ति को पीट-पीट कर मार डाला गया। राखी के दिन मुख्यमंत्री के क्षेत्र में रेप की घटना हो गई। इसे जंगल राज न कहें तो क्या कहें। यह सरकार अहंकार में डूबी हुई है। पिछले सरकार के कार्यकाल के न जाने कितने ही कामों को रोक दिया गया। केवल जेब भरने का कार्यक्रम चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले ढाई साल में सबसे ज्यादा अहित किसानों का हुआ। बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को छत्तीसगढ़ को सौंप देने का काम हो रहा है। मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, लेकिन पेसा क़ानून की राज्य में क्या हालत है? जहां खनन का काम हो रहा वहां से आदिवासी भगाए जा रहे हैं। राज्य में भू माफ़िया बढ़ गए हैं। ये पैतृक जमीनें तक छिन ले रहे हैं। अबूझमाड़ में जंगलों की कटाई शुरू हो चुकी है? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता रहा, लेकिन धान के उत्पादन में यहां के किसान खून के आंसू रो रहे हैं। जो अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ वह यह सरकार कर ले रही है। धान ख़रीदी में गड़बड़ी की लगातार शिकायतें आती रही हैं। जशपुर जिले के पचास हज़ार पंजीकृत किसानों में से आठ हज़ार किसान अपना धान नहीं बेच पाये। डॉ. महंत ने कहा कि भारतमाला परियोजना में पाँच सौ करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है। एक खसरे के कई-कई टुकड़ों में बेचा गया। हमारे पैसों में भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसका दोष मैं किसे दूँ? मनमोहन सिंह की सरकार में वनभूमि अधिनियम बना था। पट्टा देने का प्रावधान किया था। इसे भी आप नहीं कर रहे हैं। महतारी वंदन योजना की वजह से आपकी सरकार बनी। अगर ये योजना नहीं बनती तो आपका राम नाम सत्य हो गया था। बच्चों तक में शराबखोरी की लत पड़ रही है। लगता है एक महीने में एक हज़ार करोड़ रुपये की शराब पिलाकर एक नया कीर्तिमान बनाना चाह रहे हैं। एक मंत्री का वीडियो है मेरे पास, जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि शराब से जो पैसा आता है, उसे ही हम महतारी वंदन में देते हैं। डॉ. महंत ने आरोप लगाया कि ग़रीब के बच्चों को पढ़ाना बंद किया जा रहा है। दस हज़ार स्कूल बंद कर दिए गए। शिक्षकों की कमी है। एक मंत्री थे जिन्होंने कहा था कि 33 हज़ार स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होगी।

वधुओं को नकली मंगलसूत्र पहनाए जाने का मामला विधानसभा में उठा

रायपुर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में वधुओं को नकली मंगलसूत्र पहनाए जाने के मामले को कांग्रेस विधायक श्रीमती अनिला भेंडिया ने आज विधानसभा में उठाया। प्रश्नकाल में श्रीमती अनिला भेंडिया का सवाल था कि 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना' के तहत बालोद जिले में पिछले दो वर्षों में कुल कितने सामूहिक विवाह आयोजित हुए उन पर कुल कितना व्यय हुआ वित्तीय सहायता में से उपहार सामग्री और विशेष रूप से आभूषण मंगलसूत्र, बिछिया आदि के लिए प्रति जोड़ा कुल कितनी राशि निर्धारित है क्या विभाग को उपहार सामग्री की गुणवत्ता में भारी कमी और वित्तीय विसंगतियों के कारण सप्लायर फर्म के बिलों से कटौती (रिकवरी) करनी पड़ी है यदि हाँ, तो कितनी क्या उक्त फर्म को ब्लैक लिस्ट में डाला गया क्या वहाँ वितरित सामग्री की गुणवत्ता की कोई लैब टेस्टिंग या वित्तीय ऑडिट कराया गया है यदि नहीं, तो शासन इस गंभीर लापरवाही की उच्च स्तरीय या थर्ड पार्टी जांच कब तक कराएगी महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की ओर से जवाब आया कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बालोद जिले में पिछले दो वर्षों में कुल 07 सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। उन पर कुल 1 करोड़ 99 लाख 95 हजार 294 रूपये की राशि व्यय हुई। योजनांतर्गत प्रति जोड़ा उपहार सामग्री अंतर्गत श्रृंगार सामग्री हेतु राशि 7 हजार रूपये की व्यय सीमा निर्धारित है। जिसके अंतर्गत वर-वधू के कपड़े, श्रृंगार सामग्री, जूते-चप्पल, चुनरी, साफा, मंगलसूत्र इत्यादि सामग्री तथा अन्य आवश्यक सामग्री का प्रावधान है। प्रति हितग्राही मंगलसूत्र, बिछिया आदि हेतु पृथक से लागत राशि निर्धारित नहीं है। सप्लायर फर्मों के बिलों से कटौती रिकवरी जैसी स्थिति नहीं रही। वितरित सामग्री की गुणवत्ता की कोई लैब टेस्टिंग या वित्तीय ऑडिट नहीं कराया गया है। गंभीर लापरवाही के प्रकरण प्राप्त न होने से उच्च स्तरीय या थर्ड पार्टी जांच की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं है। श्रीमती अनिला भेंडिया ने कहा कि आपने गलत आंकड़े पेश किए।

चंडीगढ़ पर मां चंडी का लिया आशीर्वाद

यहां का विकास पूरे उत्तर भारत के लिए अहम-पीएम मोदी.....

चंडीगढ़/ संवाददाता

पीएम ने कहा कि चंडीगढ़ केवल एक शहर नहीं भारत के डेवलपमेंट के लिए एक मॉडल है। चंडीगढ़ की पहचान बेहतर लाइफस्टाइल, चिकित्सा सुविधा के लिए। मां चंडी के आशीर्वाद के लिए भी इसकी पहचान है। चंडीगढ़ का विकास हमेशा एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। पीएम ने कहा कि हमने देश में न्याय संहिता में बड़ा बदलाव किया। भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत चंडीगढ़ से हुई। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल, स्मार्ट पार्किंग, डिजिटल गवर्नमेंट ऐसे कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए। ढाई हजार करोड़ से ज्यादा खर्च किया। अब नए प्रोजेक्ट पर खर्च किया गया है। मोदी ने कहा कि मेरे लिए स्वच्छता अभियान, सफाई अभियान बहुत अहम है। उन्होंने चंडीगढ़ के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू की सफाई अभियान की तारीफ की। मोदी ने कहा कि मैं देख रहा था कि मेरे आने से पहले नेता शहर में सफाई अभियान चला रहे थे। मोदी ने कहा कि एक समय था, जब भारत के हेल्थ सेक्टर पर दुनिया सवाल उठाती थी। कोरोना के समय में हमने देखा कि भारत के लिए विश्व का नजरिया बदला। भारत मदद मांगने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को मदद दे रहा था। भारत मेडिकल डेस्टिनेशन बन रहा है। बारह साल पहले हमने संकल्प लिया था कि देश को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं। जेपी नड्डा ने कहा कि ये शहर पीएम का अपना शहर है, ये उनकी कर्म भूमि रही है।

महाराष्ट्र के वर्धा में नाबालिग लड़की की हत्या, यौन उत्पीड़न की आशंका, तीन गिरफ्तारी

वर्धा। महाराष्ट्र के वर्धा में नाबालिग लड़की की हत्या करने का मामला सामने आया है. उसका शव बिना कपड़ों के मिला है. इससे यौन उत्पीड़न की आशंका जताई जा रही है. गृह राज्य मंत्री ने इस मामले में तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. वर्धा जिले के सवांगी पुलिस स्टेशन थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 साल की एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पत्थर से कुचलकर मार डाला गया. चूंकि उसकी बिना कपड़ों की बॉडी एक फार्महाउस में मिली, इसलिए सेक्सुअल असॉल्ट का भी शक है. इस घटना से इलाके में गुस्सा फैल गया है और गांव में तनाव का माहौल है. इस बीच, गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा, इस घटना के बारे में केस दर्ज कर तीन संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सोनम वांगचुक का नया वीडियो सामने आया

मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा उसके बाद भूत बनकर आऊंगा

नई दिल्ली/ एजेंसी

कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी समर्थन दे रहे हैं। सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर है। कांग्रेस समेत कई पार्टियों के नेता ने सोनम वांगचुक से मुलाकात कर उनके प्रदर्शन को समर्थन दिया है। इस बीच वांगचुक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सोनम वांगचुक कर रहे हैं कि मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर आप लोगों के बीच आऊंगा। वांगचुक ने यह बात मजाकिया अंदाज में कही। संसद तक की मार्च का जिक्र करते हुए सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, जिससे आप सभी के साथ संसद तक मार्च कर सकूं। अगर 20 जुलाई को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो फिर भूतकर बनकर वापस आऊंगा। बता दें कि नीट परीक्षा लीक और सीबीएसई विवाद को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहा है। लद्दाख के इंजीनियर, शिक्षाविद् और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून को इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तभी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। लगातार भूखे रहने के कारण उनका वजन लगातार घट रहा है।

बिलासपुर में 20 साल बाद बाढ़ जैसे हालात

मूसलाधार बारिश से सड़कें और घर जलमग्न,पांच ट्रेनें रद्द हुए

- एसडीआरएफ ने 40 से अधिक लोगों का किया रेस्क्यू

बिलासपुर। संवाददाता

बिलासपुर में गुरुवार रात से शुक्रवार दोपहर तक लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। करीब 20 साल बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। लगातार बारिश के कारण शहर के अधिकांश इलाके पानी में डूब गए हैं। सड़कों से लेकर कॉलोनियों तक जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है, जबकि रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से 5 मेमू ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 3 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान औसतन 74.7 मिमी बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 110.2 मिमी वर्षा सीपत क्षेत्र में रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार लगातार हो रही बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। सरकंडा और चांटीडीह के निचले इलाकों में पानी तेजी से भरने के कारण 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सरकंडा के बंधवापारा क्षेत्र में एसडीआरएफ की टीम ने दो नावों की

मदद से राहत एवं बचाव अभियान चलाया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं, दोमुहानी इलाके में 10 से अधिक घर चारों ओर से पानी से घिर गए, जिससे कई परिवार पूरी रात अपने घरों में फंसे रहे। प्रशासन को सूचना मिलने के बाद राहत दल मौके पर पहुंचा और लोगों को सुरक्षित निकालने की कार्रवाई शुरू की गई। शहर के कई हिस्सों में ट्रांसफॉर्मर पानी में डूब जाने से बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। कई इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। बिजली आपूर्ति ठप होने से पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित हुई है और लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग की टीमें हालात सामान्य करने में जुटी हुई हैं। भारी बारिश का असर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी दिखाई दिया। बिलासपुर कलेक्टर के सरकारी बंगले में भी पानी भर गया, जिसके बाद नगर निगम की टीम को जल निकासी के लिए लगाया गया। नगर निगम की मशीनें लगातार पानी निकालने का काम कर रही हैं ताकि स्थिति जल्द सामान्य हो सके।

नेशनल हाईवे पर भी जलभराव, वाहनों की लगी लंबी कतार

बिलासपुर-जांजगीर नेशनल हाईवे पर दरीघाट के पास बारिश का पानी भर जाने से यातायात प्रभावित हो गया। मूसलाधार बारिश के बीच वाहनों की लंबी कतार लग गई। राहगीरों ने जलभराव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं अपोलो हॉस्पिटल के पास भी जलभराव के कारण लोग घंटों तक फंसे रहे। काफी मशक्कत के बाद लोग सुरक्षित बाहर निकल सके। बारिश थमने के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे, हालांकि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला अधिवक्ता संघ ने मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि शुक्रवार को बारिश के कारण किसी भी मामले में प्रतिकूल आदेश पारित न किए जाएं।

नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय से हिन्दू जागरण मंच ने की सौजन्य भेंट

धमतरी। हिन्दू जागरण मंच जिला धमतरी के जिला संयोजक पुरुषोत्तम निषाद के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने जिले की नवपदस्थ जिला पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय से मुलाकात कर उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया तथा नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं। इस अवसर पर हिन्दू जागरण मंच के प्रतिनिधिमंडल ने जिले से जुड़े विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर जिला पुलिस अधीक्षक का ध्यान आकृष्ट कराया। आगामी श्री गणेश स्थापना एवं गणेश उत्सव के संबंध में चर्चा करते हुए प्रतिनिधिमंडल ने सनातन धर्म की मूल परंपरा के अनुरूप मिट्टी से निर्मित गणेश प्रतिमाओं को बढ़ावा देने तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की मांग रखी। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि मिट्टी की प्रतिमाएं पर्यावरण के संरक्षण के साथ-साथ भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के अनुरूप भी हैं। जिला पुलिस अधीक्षक भावना पाण्डेय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना तथा सामाजिक सौहार्द्र, कानून व्यवस्था एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए समाज के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। मुलाकात के दौरान हिन्दू जागरण मंच के पदाधिकारियों ने संगठन द्वारा समाजहित, राष्ट्रहित, गौ-संरक्षण, सांस्कृतिक जागरण एवं सनातन मूल्यों के संरक्षण हेतु किए जा रहे विभिन्न कार्यों से भी जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया। इस अवसर पर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य युवा आयाम दीपक सिंह ठाकुर, जिला सहसंयोजक चित्रेश साहू, डाकेश्वर साहू, प्रतीक सोनी, सनत साहू, युवा आयाम जिला संयोजक सत्यम सिन्हा, नगर संयोजक अभिषेक साहू, नगर सहसंयोजक संजय साहू एवं शिवांश पटवा उपस्थित रहे।

शहर की यातायात व्यवस्था का किया निरीक्षण

धमतरी पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय ने शहर के प्रमुख चौक-चौराहों का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बढ़ते यातायात दबाव, पार्किंग व्यवस्था, जाम की स्थिति एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यातायात व्यवस्था को और अधिक सुचारु एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने यातायात प्रभारी को नियमित मॉनिटरिंग, प्रमुख चौक.चौराहों पर प्रभावी ड्यूटी, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने तथा आमजन को सुरक्षित एवं सुगम यातायात उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था में सुधार धमतरी पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए निरंतर प्रभावी प्रयास किए जाएंगे। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक ने थाना सिटी कोतवाली धमतरी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीसीटीएनएस कार्य, थाना अभिलेखों के संधारण, मालखाना, कार्यालयीन व्यवस्थाओं, थाना परिसर एवं भवन की साफ-सफाई का अवलोकन किया तथा अभिलेखों को अद्यतन रखने, कार्यालयीन कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने एवं थाना परिसर को स्वच्छ एवं व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि थाना परिसर में आने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ संवेदनशील, विनम्र एवं पेशेवर व्यवहार सुनिश्चित किया जाए तथा जनसमस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार पांडेय, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार चतुर्वेदी, यातायात डीएसपी मोनिका साहू, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक राजेश जगत तथा यातायात प्रभारी के आर साहू उपस्थित रहे।

किसानों को समय पर मिल रहे खाद बीज, खेती को मिली रफ्तार

गरियाबंद। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सहकारी समितियों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही वितरण व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और किसान हितैषी बनाते हुए टोकन प्रणाली समाप्त कर आवश्यकतानुसार एकमुश्त खाद एवं बीज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इससे किसानों का समय बच रहा है तथा उन्हें बार-बार समिति के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। शासन द्वारा सभी सहकारी समितियों में खाद एवं बीज का नियमित भंडारण, उपलब्धता की सतत निगरानी तथा मांग के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, ताकि खरीफ की बुवाई समय पर पूरी हो सके। किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

अजय यादव को आईजी नियुक्त होने पर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने दी बधाई

सरायपाली। यादव समाज के गौरव छत्तीसगढ़ कैडर के वर्ष 2004 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी अजय यादव को राजनांदगाँव रेंज का पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) नियुक्त किए जाने एवं पदभार ग्रहण करने पर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के पदाधिकारियों ने उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। यादव ने अपने पुलिस सेवा काल में विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी एवं सशक्त कार्य किया है। वे मेनूवल पुलिसिंग में महारथ हासिल है कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते हैं। उन्हें उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय वीरता पदक तथा सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। अजय यादव ने पुलिस अधीक्षक के रूप में नारायणपुर, कांकेर, बिलासपुर, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, दुर्ग तथा रायपुर सहित विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएँ दी हैं। इसके बाद वे सरगुजा रेंज के आईजी, रायपुर रेंज के आईजी, आईजी (इंटेलिजेंस) तथा बिलासपुर रेंज के आईजी के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में पुलिस मुख्यालय, रायपुर में पदस्थ रहने के उपरांत उन्हें राजनांदगाँव रेंज का आईजी नियुक्त किया गया है। उनके पदभार ग्रहण करने पर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के राष्ट्रीय सचिव इंजी. एस.डी. यादव, प्रदेश अध्यक्ष भुनेश्वर यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं मीडिया प्रभारी नरेन्द्र कुमार यादव, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ममता यादव, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव नारद यादव (बेमेतरा), जितेंद्र यादव (बिलासपुर), धनेश यादव (ब्लॉक अध्यक्ष, बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़), राजेंद्र यादव (जिला अध्यक्ष, सारंगढ़), विनोद यादव (जिला अध्यक्ष, महासमुंद), कार्यकारी जिला अध्यक्ष डॉ. पवन यादव, दिनेश कुमार यादव, राजेंद्र कुमार यादव (राजू), मयंक यादव, तुषार यादव (सरायपाली) तथा आर.के. यादव, महेश यादव, अनिल यादव (जिला अध्यक्ष, रायपुर), नागेश यादव एवं चन्दन यादव सहित अनेक पदाधिकारियों ने उन्हें उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं।

संपर्क केंद्र की तत्परता से महाराष्ट्र में बिछड़े 15 वर्षीय बालक सकुशल परिवार से मिला

बलौदाबाजार-भाटापारा। संचालित जिला संपर्क केंद्र की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी समन्वय से महाराष्ट्र में अपने परिवार से बिछड़ा 15 वर्षीय बालक सालिक राम ध्रुव सकुशल अपने माता-पिता से मिल गया। बालक के सुरक्षित घर लौटने पर परिवार की खुशियां लौट आई और भावुक माता-पिता ने जिला प्रशासन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गिन्दोला, तहसील लवन निवासी दुलेश ध्रुव अपने परिवार सहित वर्तमान में कामठी (महाराष्ट्र) में मजदूरी कार्य करते हैं। इसी दौरान उनका 15 वर्षीय पुत्र सालिकराम ध्रुव अचानक परिवार से बिछड़ गया। कामठी थाना क्षेत्र में अकेले घूमते हुए पाए जाने पर स्थानीय पुलिस ने बालक को संरक्षण में लिया और उससे पूछताछ कर उसके परिजनों के संबंध में जानकारी जुटाई। जानकारी के आधार पर कामठी पुलिस ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में संचालित संपर्क केंद्र के हेल्पलाइन नंबर 9201899925 पर संपर्क कर घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही संपर्क केंद्र की टीम ने तत्काल सक्रिय होकर संबंधित अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया तथा ग्राम गिन्दोला पहुंचकर बालक के परिजनों की प्रामाणिकता का सत्यापन कराया। इसके बाद सभी आवश्यक वैधानिक प्रक्रियाएं एवं काउंसलिंग पूरी कर बालक सालिकराम ध्रुव को सुरक्षित उसके माता-पिता के सुपुर्द किया गया। कई दिनों बाद अपने बेटे को सकुशल सामने देखकर माता-पिता की आंखें खुशी से नम हो गईं। उन्होंने जिला प्रशासन की संवेदनशील कार्यप्रणाली, संपर्क केंद्र की तत्परता तथा कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में किए गए मानवीय प्रयासों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन की सक्रियता के कारण उनका बिछड़ा हुआ बेटा सुरक्षित वापस मिल सका।

कलेक्टर उइके ने स्लिट लैंप आई टेस्टिंग मशीन का किया शुभारंभ

गरियाबंद। जिला चिकित्सालय में कलेक्टर बीएस उइके की उपस्थिति में आधुनिक स्लिट लैंप आई टेस्टिंग मशीन का शुभारंभ किया गया। यह अत्याधुनिक मशीन आईडीबीआई बैंक द्वारा अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के अंतर्गत जिला चिकित्सालय को प्रदान की गई है। इस मशीन के स्थापित होने से जिले के मरीजों को नेत्र परीक्षण की बेहतर एवं आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी तथा गंभीर नेत्र रोगों की समय रहते पहचान और उपचार में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर कलेक्टर बीएस उइके ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आईडीबीआई बैंक ने जिले के मरीजों को ध्यान में रखते हुए स्वप्रेरणा से जिला चिकित्सालय को यह आधुनिक मशीन उपलब्ध कराई है, जो सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि नवीनतम तकनीक से युक्त इस मशीन के माध्यम से जिले के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की नेत्र जांच सुविधा स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होगी और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। कलेक्टर उइके ने स्वयं स्लीट लैंप मशीन से अपनी आंखों की जांच कराकर मशीन का शुभारंभ किया तथा इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी भी प्राप्त की। कार्यक्रम के दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. टीसी पात्रा ने स्लीट लैंप मशीन की उपयोगिता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह अत्याधुनिक आई टेस्टिंग मशीन है। जिसके माध्यम से आंख के बाहरी भाग, कॉर्निया, लेंस, रेटिना तथा आंख की अन्य सूक्ष्म संरचनाओं की विस्तृत एवं सटीक जांच की जा सकती है। इस मशीन से आंखों के बारीक से बारीक रोगों का प्रारंभिक स्तर पर पता लगाया जा सकता है, जिससे समय पर उपचार संभव हो सकेगा। उन्होंने बताया कि यह उपकरण नेत्र शल्य चिकित्सा से पहले और बाद की जांच के साथ-साथ ऑपरेशन थियेटर में भी काम आएगा। आईडीबीआई बैंक भिलाई के क्षेत्रीय प्रबंधक अकुल्य कल्याण ने कहा कि बैंक अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत जनहित एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय को स्लीट लैंप आई टेस्टिंग मशीन उपलब्ध कराना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस आधुनिक मशीन से मरीजों को बेहतर नेत्र जांच की सुविधा मिलेगी तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। उन्होंने भविष्य में भी जनकल्याणकारी कार्यों में जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग जारी रखने की बात कही। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यूएस नवरत्न ने बताया कि इस आधुनिक मशीन के उपलब्ध होने से जिला चिकित्सालय की नेत्र चिकित्सा सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। मरीजों की सटीक जांच, शीघ्र रोग पहचान एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने में यह मशीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथ ही गंभीर मामलों को समय रहते चिन्हित कर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा सकेगा।

महावीर इंटरनेशनल संस्था के स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

धमतरी। डॉक्टर डे और सीए डे का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें डॉक्टर यश भोमराज छाजेड़ और सीए हर्ष निलेश पारख का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महावीर वीरा ग्रुप की महिलाओं का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर वीरा नीलू लुणावत, वीरा मधु बैद, वीरा अनीता कुकरेजा, वीरा शोभा बैद, वीरा अनीता लुणावत, वीरा मोना शाह, वीरा कल्पना लुणावत आदि उपस्थित थे। महावीर इंटरनेशनल वीरा शाखा द्वारा नवजात शिशुओं के लिए बेबी किट का वितरण भी किया गया। महावीर इंटरनेशनल वीरा केंद्र धमतरी द्वारा संस्था के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में तृतीय सोपान जिसमें संस्था की महत्वाकांक्षी वात्सल्य योजना शासकीय जिला अस्पताल में 50 नवजात शिशु को बेबी किट का वितरण किया गया। इसमें निम्न सदस्यों की उपस्थिति रही, उपाध्यक्ष वीरा अनिता कुकरेजा, सचिव वीरा मधु बैद, कोषाध्यक्ष वीरा अनीता लूनावत, वीरा शोभा बैद, सहसचिव वीरा संजु बड़जात्या आदि सदस्य उपस्थित थे। संस्था की शीर्ष केंद्र द्वारा नवजात शिशुओं को संक्रमण से बचाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

सीएम हेल्पलाइन बनी उम्मीद की नई राह, व्हीलचेयर मिलने से पटरी पर लौटी नूतन की जिंदगी

बलौदाबाजार। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर शुरू किये गये सीएम हेल्पलाइन 1076 से लोगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन से दिव्यांग नूतन कुमार रजक को व्हीलचेयर मिला जिससे उसके कई कार्य आसान हो गया। ग्राम अर्जुनी स्थित बजरंग चौक शीतला मंदिर के पास रहने वाले 32 वर्षीय नूतन कुमार रजक का जीवन वर्ष 2025 में एक सड़क दुर्घटना के बाद पूरी तरह बदल गया। हादसा इतना गंभीर था कि उनके दोनों पैर काटने पड़े। इस घटना ने न केवल उनकी शारीरिक क्षमता छीन ली, बल्कि घर से लगे छोटे से जनरल स्टोर तक पहुंचना भी उनके लिए बेहद कठिन हो गया। रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम भी दूसरों की मदद के बिना संभव नहीं रह गए। ऐसे कठिन समय में एक दिन उन्होंने समाचार पत्र में सीएम हेल्पलाइन के बारे में पढ़ा। उनके मन में उम्मीद जगी कि शायद उनकी समस्या का भी समाधान इस माध्यम से हो सके। उन्होंने बिना देर किए हेल्पलाइन नंबर 1076 पर संपर्क किया। वहां उनकी बात गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुनी गई तथा उन्हें सकारात्मक आश्वासन मिला। इसके बाद समाज कल्याण विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज एक सप्ताह के भीतर उन्हें व्हीलचेयर उपलब्ध करा दी। व्हीलचेयर मिलने से अब नूतन कुमार रजक के लिए अपने जनरल स्टोर तक पहुंचना आसान हो गया है और वे फिर से आत्मविश्वास के साथ अपना काम संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सहायता उनके लिए केवल एक व्हीलचेयर नहीं, बल्कि नई जिंदगी और आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाला एक प्रभावी और भरोसेमंद माध्यम बन गया है, जिसने उनके जीवन में फिर से उम्मीद की रोशनी जगा दी।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख रुपये की दावा राशि का चेक प्रदान किया गया

गरियाबंद। कलेक्टर बीएस उइके ने अपने कार्यालय कक्ष में गरियाबंद विकासखंड के ग्राम धवलपुर निवासी दिवंगत नितेश साहू की नामांकित हितग्राही सोमा साहू को 02 लाख रुपये की दावा राशि का चेक सौंपा। भारत सरकार की जनकल्याणकारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गरियाबंद द्वारा चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबंधक के.एम. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। जिसके तहत मात्र 436 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर दो लाख रुपये का जीवन बीमा सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि दिवंगत नितेश साहू ने बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा गरियाबंद के माध्यम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अपना पंजीयन कराया था। उनके आकस्मिक निधन के उपरांत योजना के प्रावधानों के अनुसार उनकी नामांकित सदस्य सोमा साहू को दो लाख रुपये की बीमा दावा राशि स्वीकृत कर प्रदान की गई। कलेक्टर बीएस उइके ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि जरूरत के समय परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके।

पीओपी निर्मित देवी-देवताओं की मूर्तियां हो प्रतिबंधित : हिंदू जागरण मंच

धमतरी। हिन्दू जागरण मंच जिला धमतरी ने सनातनी परम्पराओं से ही गणेश जी की प्रतिमा निर्माण हेतु मूर्तिकार संघ एवं कुम्हार समाज के आग्रह पर कलेक्टर धमतरी, जिला अनुविभागीय अधिकारी, आयुक्त नगर निगम, पुलिस अधीक्षक धमतरी के नाम पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में कहा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित देवी.देवताओं की मूर्तियों के निर्माण एवं विक्रय पर प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित कराने तथा उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु आवेदन किया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्तियों के निर्माण, विक्रय एवं विसर्जन से जल प्रदूषण तथा पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुँचती है। इसी उददेश्य से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय.समय पर पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों के निर्माण एवं विसर्जन संबंधी दिशा.निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा.निर्देशों में प्राकृतिक मिट्टी एवं पर्यावरण.अनुकूल सामग्री से मूर्तियाँ बनाने पर बल दिया गया है। अतः निम्नलिखित वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही किए जाने की मांग की है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, धारा 3 पर्यावरण संरक्षण हेतु केंद्र सरकार की शक्तियाँ। धारा 5 पर्यावरण संरक्षण हेतु निर्देश जारी करने की शक्ति, धारा 15 अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत जारी आदेशों/निर्देशों के उल्लंघन पर दंड। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण रोकने एवं जल स्रोतों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी तथा पर्यावरण-अनुकूल मूर्तियों के निर्माण संबंधी दिशा.निर्देश। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पारित पर्यावरण संरक्षण संबंधी आदेशों का पालन। हिंदू जागरण मंच ने कहा कि जिले में पीओपी की मूर्तियों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय की जांच कराई जाए तथा यदि कोई व्यक्ति या संस्था लागू आदेशों एवं पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएँ, तो उनके विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 तथा अन्य लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर पुरुषोत्तम निषाद जिला संयोजक, डाकेश्वर साहू, , प्रान्त युवा आयाम प्रमुख एवं कार्यकारिणी सदस्य, हिन्दू जागरण मंच, छत्तीसगढ़ ने सूचना सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

महापौर के प्रयासों से पुल-पुलिया निर्माण के लिए राशि स्वीकृत

धमतरी। बाढ़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से चली आ रही आवागमन की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। महापौर जगदीश रामू रोहरा के सतत प्रयासों से सेमरा बी, कोड़ेगांव, ढीमरटुकुर, मोंगरागहन एवं सेहराडाबरी में पुल.पुलिया निर्माण कार्यों के लिए 44 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति से बरसात के दौरान संपर्क मार्ग बाधित होने की समस्या दूर होगी तथा हजारों ग्रामीणों को वर्षभर सुरक्षित, सुगम और निर्बाध आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। महापौर रामू रोहरा ने इन बाढ़ प्रभावित गांवों की समस्या को लगातार शासन के समक्ष प्रमुखता से उठाया और ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा कराने के लिए निरंतर प्रयास किए। उनके जनहितकारी प्रयासों और सकारात्मक पहल के परिणामस्वरूप शासन द्वारा यह महत्वपूर्ण स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत राशि से क्षतिग्रस्त पुल.पुलियों का पुनर्निर्माण तथा आवश्यक स्थानों पर नई पुल-पुलियों का निर्माण कराया जाएगा। इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार तथा दैनिक आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन में होने वाली परेशानियों से स्थायी राहत मिलेगी। विशेष रूप से बरसात के मौसम में गांवों का संपर्क टूटने की समस्या समाप्त होगी, जिससे विद्यार्थियों, किसानों, मरीजों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। महापौर रामू रोहरा ने इस जनहितकारी स्वीकृति के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद रूप कुमारी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की है और इसी सोच के अनुरूप प्रदेशभर में विकास कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। महापौर रोहरा ने कहा कि धमतरी विधानसभा सहित नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। जनता की प्रत्येक आवश्यक मांग को शासन तक पहुंचाकर उसका शीघ्र समाधान कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में भी क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति मिलेगी, जिससे धमतरी जिले के विकास को नई गति और नई दिशा प्राप्त होगी।

भिलाई निगम की नई आयुक्त ने संभाला मोर्चा, स्वच्छता और व्यवस्थाओं का जायजा

जोन 1 और जोन 2 के एसएलआरएम सेंटरों, कोसा नाला, गोठान और नवनिर्मित डॉग हाउस का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई की नव-नियुक्त आयुक्त सुरूचि सिंह ने कार्यभार संभालते ही शहर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए मैदानी स्तर पर निरीक्षण शुरू कर दी है। इसी कड़ी में उन्होंने निगम के जोन 1 और जोन 2 अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों का सघन दौरा किया और विकास कार्यों सहित स्वच्छता व्यवस्था का जायजा ली हैं। आयुक्त ने अपने दौरे की शुरुआत जोन 1 नेहरू नगर अंतर्गत संचालित एसएलआरएम सेंटर से की हैं। वहां उन्होंने कचरा पृथक्करण की प्रक्रिया को देखी और स्वच्छता दीदियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं व कार्यप्रणाली की जानकारी ली। इसके पश्चात, उन्होंने एम. जे. कॉलेज के समीप स्थित कोसा नाला का निरीक्षण किये। वर्षा ऋतु के मद्देनजर उन्होंने नाले की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। जोन 1 के बाद निगम आयुक्त जोन 2 का रुख कर यहाँ उन्होंने एसएलआरएम सेंटर केंद्र की कचरों के निपटान की क्षमता और स्वच्छता मानकों की समीक्षा की। नवनिर्मित डॉग हाउस में आवारा कुत्तों के सुव्यवस्थित रखरखाव और उनके टीकाकरण/बंध्याकरण के लिए बनाए गए नए डॉग हाउस का बारीकी से निरीक्षण कर और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किये हैं। गोठान की व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने मवेशियों के लिए चारे-पानी के साथ अन्य पुख्ता इंतजाम हेतु निर्देश दिये हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता अजीत कुमार तिग्गा, उपायुक्त सह जोन आयुक्त डी के कोसरिया, जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे, कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल, अरविंद शर्मा, सहायक अभियंता फत्तेलाल साहू, श्वेता माहेश्वर, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, उप अभियंता शंकर सुवन मरकाम, पुरुषोत्तम सिन्हा, रीमा जामुलकर, चंदन निर्मल, सहायक राजस्व अधिकारी सुनील जोशी, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, शंकर साहनी सहित निगम का अमला उपस्थित रहा।

कैजुअल्टी में दो डॉक्टर होंगे अपॉइंट, सीटी स्कैन के लिए मिलेंगे दो टेक्निशियन

कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का किया निरीक्षण

राजनांदगांव। कलेक्टर जितेन्द्र यादव ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव का निरीक्षण कर विभिन्न विभागों एवं वार्डों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने रेडियोलॉजी विभाग का निरीक्षण कर प्रतिदिन होने वाले सीटी स्कैन एवं सोनोग्राफी की संख्या तथा विभाग में आने वाली समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) मद से दो सीटी स्कैन टेक्नीशियन की भर्ती हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मरीजों से चर्चा कर उपचार की ली जानकारी

कलेक्टर ने कैजुअल्टी वार्ड का निरीक्षण किया तथा वहां भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से चर्चा कर मेडिकल कालेज में मिल रही चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मरीजों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैजुअल्टी वार्ड में दो मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नियोनेटल वार्ड का भी निरीक्षण किया। उन्होंने चिलर प्लांट में आवश्यक सुधार करने तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का विस्तार करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों को दिए निर्देश

उन्होंने इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर एवं इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. पी.एम. लूका, अधीक्षक डॉ. अतुल देशकर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवतरन तथा डॉ. पवन जेठानी सहित अन्य चिकित्सा, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

श्रम कानूनों का उल्लंघन, 6 उद्योगों पर एफआईआर

औद्योगिक स्वास्थ्य व सुरक्षा विभाग की सघन जांच

कई प्रतिष्ठानों में मिली अनियमितताएं

रायगढ़। कलेक्टर के निर्देश पर जिले में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं कार्यस्थल पर निर्धारित मानकों के पालन को लेकर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। कार्यालय उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायगढ़ के उप संचालक राहुल पटेल के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न कारखानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कई इकाइयों में श्रम एवं सुरक्षा संबंधी नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मई एवं जून 2026 के दौरान कुल छह आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय रायगढ़ में दायर किए हैं। कार्रवाई कारखाना अधिनियम 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 के प्रावधानों के तहत की गई है। माह मई के दौरान मेसर्स अग्रोहा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम पाली के अधिभोगी उत्तम कुमार अग्रवाल, मेसर्स जिंदल स्टील लिमिटेड यूनिट-3 के अधिभोगी देबोज्योति रॉय तथा मेसर्स रायगढ़ साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्रा.लि. के अधिभोगी सरोज कुमार पाथी के विरुद्ध उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 के प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किए गए। इसी प्रकार मेसर्स रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्रा.लि. यूनिट-2 के संचालक विकास कुमार अग्रवाल तथा बीपी एक्टिव इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक बिमल कुमार भगत के विरुद्ध भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम एवं संबंधित नियमों के उल्लंघन के कारण कार्रवाई की गई। वहीं जून 2026 में मेसर्स शिव शक्ति स्टील लिमिटेड के अधिभोगी संजय घोष एवं कारखाना प्रबंधक अरविंद कुमार मिश्रा के विरुद्ध श्रमिक सुविधाओं से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन पर प्रकरण दर्ज किए गए।

भिलाई निगम की बड़ी कार्रवाई: सुपेला परदेशी चौक में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सड़क हुई अतिक्रमण मुक्त

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई ने शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। निगम की संयुक्त टीम ने सुपेला स्थित परदेशी चौक के पास संचालित व्यापारियों द्वारा दुकानों के सामने किए गए अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया। निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि व्यापारियों द्वारा दुकानों के सामने सड़क तक सामान एवं अन्य सामग्री रखकर सार्वजनिक मार्ग पर कब्जा कर लिया गया है। इससे सड़क संकरी हो गई थी और राहगीरों तथा वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई ने सख्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान जोन-1 उपायुक्त सह जोन आयुक्त डी के कोसरिया, जोन आयुक्त अमरनाथ दुबे, सहायक राजस्व अधिकारी सुनील जोशी, बेदखली प्रभारी विनय शर्मा, राजस्व विभाग, बेदखली अमला तथा पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर मौजूद रही। टीम ने जेसीबी की सहायता से सड़क पर किए गए अवैध कब्जों को हटाकर मार्ग को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की तैनाती के कारण अभियान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़कों एवं फुटपाथों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागरिकों की सुविधा और निर्बाध यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

निगम ने व्यापारियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें और शहर को व्यवस्थित एवं सुगम बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।

नमस्ते दिवस पर स्वच्छता दीदियों का सम्मान, सुरक्षा उपकरण वितरण एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित

भिलाईनगर। नमस्ते दिवस के अवसर पर नगर पालिक निगम भिलाई के जोन-1 नेहरू नगर स्थित एसएलआरएम सेंटर में कार्यरत स्वच्छता दीदियों के सम्मान एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उपकरणों का वितरण किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता दीदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक परामर्श प्रदान किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त सह जोन आयुक्त दिनेश कोसरिया ने कहा कि स्वच्छता दीदियां शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखना निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी स्वच्छता कर्मियों से सुरक्षा उपकरणों का नियमित उपयोग करने तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की अपील की। इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने स्वच्छता कर्मियों को स्वच्छता के साथ-साथ व्यक्तिगत सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी प्रदान की। जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना ने भी सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की जानकारी देते हुए नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पी.आई.यू अभिनव ठोकनेए सुभम पाटनी एवं ए.पी.एम. सहित निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने स्वच्छता दीदियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ एवं सुरक्षित कार्य वातावरण के लिए निगम द्वारा निरंतर प्रयास किए जाने की बात कही।

यूरिया संकट गहराया, किसान परेशान और कृषि केंद्रों में मनमानी कीमत वसूली के आरोप

कवर्धा। खरीफ सीजन के चरम दौर में कबीरधाम जिले में यूरिया खाद की किल्लत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिले के विभिन्न सहकारी समितियों एवं निजी कृषि केंद्रों में यूरिया की उपलब्धता सीमित होने से किसानों को घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर निजी कृषि केंद्रों द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर यूरिया बेचने और किसानों को जबरन अन्य कृषि उत्पाद खरीदने के आरोप भी सामने आ रहे हैं। धान की फसल में इस समय टॉप ड्रेसिंग(रोपाई) के लिए यूरिया की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन जिले के कई क्षेत्रों में किसान पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलने से परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि कई निजी विक्रेता यूरिया खाद के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व, कीटनाशक या अन्य उत्पाद खरीदने का दबाव बना रहे हैं। इससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि उर्वरक आदेश, 1985 के तहत निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बेचना, कृत्रिम कमी उत्पन्न करना अथवा टैगिंग कर अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य करना नियम विरुद्ध है। इसके अलावा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी और निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती है। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा नीम कोटेड यूरिया का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) प्रति 45 किलोग्राम बैग लगभग 266 से 270 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके बावजूद कई स्थानों पर किसानों से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। यदि इन आरोपों में सत्यता पाई जाती है तो यह सीधे तौर पर उर्वरक नियंत्रण आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर उर्वरक विक्रेताओं की जांच, स्टॉक सत्यापन एवं बिक्री रजिस्टर की निगरानी के निर्देश दिए जाते रहे हैं। नियमों के अनुसार प्रत्येक विक्रेता को अपने प्रतिष्ठान में उपलब्ध स्टॉक, दर सूची एवं लाइसेंस संबंधी जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। इसके बावजूद यदि किसानों को निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो यह निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। जिले में यूरिया की मांग बढ़ने के बीच प्रशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर प्रभावी अंकुश लगाने की है। किसान संगठनों ने मांग की है कि जिला प्रशासन तत्काल विशेष जांच अभियान चलाकर निजी कृषि केंद्रों के स्टॉक, बिक्री रजिस्टर एवं मूल्य सूची की जांच कराए तथा दोषी पाए जाने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। खरीफ सीजन के महत्वपूर्ण समय में यूरिया की कमी और महंगे दामों पर बिक्री के आरोपों ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। यदि समय रहते स्थिति नहीं सुधरी तो इसका सीधा असर जिले में धान उत्पादन और किसानों की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन किसानों की इस गंभीर समस्या पर कितनी तत्परता से कार्रवाई करता है।

स्कूल में मधुमक्खियों का हमला: 72 विद्यार्थी हताहत

स्वास्थ्य विभाग की तत्परता से सभी विद्यार्थी सुरक्षित

डोंगरगांव नगर। ब्लॉक के ग्राम बीजेभाठा हाईस्कूल में मंगलवार को मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। घटना लगभग 11 बजे की है। मधुमक्खियों ने अकस्मात ही हमला करते हुए स्कूल के 10वीं के लगभग 72 विद्यार्थियों को डंक मार दिया। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने तत्परता दिखाते हुए स्कूल परिसर व सीएचसी में उपचार कर तात्कालिक राहत दी। सभी विद्यार्थी खतरे से बाहर बताए गए हैं। दरअसल बीजेभाठा में स्थित स्कूल के पीछे में मधुमक्खियों के छत्ते से अचानक मधुमक्खियां उड़कर कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों पर हमला कर दिया। अकस्मात हुए हमले से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान 72 छात्र व छात्राओं को मधुमक्खियों ने डंक मार दिया था। घटना होते ही स्कूल प्रबंधन ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी। बीएमओ ने तत्काल ही एक डॉक्टर, 2 नर्स वी एक ड्रेसर की टीम भेजकर अस्थाई कैंप लगाया। कैंप में कम हताहत विद्यार्थियों का डॉ धर्मेंद्र मंडावी, नर्स ज्योति ठाकुर व लता मंडावी द्वारा तत्कालिक उपचार कर आवश्यक दवाइयां देकर राहत दी गई। इधर अधिक हताहत 32 विद्यार्थियों को तत्काल ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराकर स्वयं बीएमओ डॉ रागिनी चंद्रा ने कमान संभालते हुए बच्चों का परिजन की भांति स्नेहपूर्वक उपचार किया। हॉस्पिटल में आवश्यक उपचार के उपरांत सभी विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए। विद्यार्थियों को समय पर उपचार मिलने से सभी विद्यार्थी सुरक्षित हैं। फिलहाल खबर लिखे जाने तक विद्यार्थियों को खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम के दौरान बीएमओ डॉ रागिनी चंद्रा के अलावा समस्त डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ एवं स्वास्थ्यकर्मियों ने सेवा भावना के साथ कार्य किया।

प्रशासन ने ली विद्यार्थियों की सुध

घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम अनिकेत साहू एवं तहसीलदार कमल किशोर साहू भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने स्कूल व अस्पताल में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग से बच्चों के उपचार की जानकारी लेकर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अंत में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के भी पहुंचने की खबर है।

21 स्कूलों में पहुंच मार्ग नहीं, 106 भवन जर्जर, विधानसभा में उठा मुद्दा

कवर्धा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने अपने विधानसभा क्षेत्र एवं कबीरधाम जिले से जुड़े पेयजल, नगरीय जलापूर्ति और शिक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से सदन में उठाया। विधायक ने वनांचल एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन की प्रगति, नगरीय क्षेत्रों में जल आवर्धन योजनाओं की स्थिति तथा विद्यालयों की जर्जर अधोसंरचना को लेकर सरकार से जवाब मांगा। भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के तेलियापानी लेदरा, बिरहुलडीह, कांदावाणी, छिंदीडीह, सेन्दुरखार, अमनिया, भेलकी सहित 35 से अधिक वनांचल एवं आदिवासी बहुल ग्रामों में लगभग 2,500 से अधिक परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लिखित जवाब में बताया कि कई ग्रामों में सोलर आधारित जल प्रदाय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि बसुलाटोला, तेलियापानी धोबे, कोटपानी, कांदावानी, सारपानी, छिंदीडीह, सेंदुरखार सहित कई गांवों में कार्य अभी निर्माणाधीन है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन 2.0 के तहत समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जा रही है, हालांकि पूर्णता की संभावित तिथि फिलहाल निर्धारित नहीं की जा सकती। विधायक ने नगर पालिका पंडरिया एवं नगर पंचायत पांडातराई की जल आवर्धन योजनाओं पर भी सवाल उठाए। सरकार ने बताया कि पंडरिया में 8 करोड़ 32 लाख 46 हजार रुपये तथा पांडातराई में 3 करोड़ 75 लाख 42 हजार रुपये की योजनाएं स्वीकृत की गई थीं। पंडरिया में अधिकांश कार्य पूर्ण कर 2,170 परिवारों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, जबकि नवगठित वार्डों सहित अन्य क्षेत्रों में अब भी बोरवेल के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। वहीं पांडातराई में सम्पवेल के क्रियाशील नहीं होने एवं राइजिंग मेन पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण जल आवर्धन योजना अभी तक पूरी तरह संचालित नहीं हो पाई है। स्कूल शिक्षा से जुड़े प्रश्नों के जवाब में शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने स्वीकार किया कि विगत तीन वर्षों में कबीरधाम जिले के विद्यालयों की अधोसंरचना एवं पहुंच मार्गों का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि जिले में 21 विद्यालय ऐसे हैं, जिनके पहुंच मार्ग नहीं हैं अथवा अत्यंत जर्जर स्थिति में हैं। इसके अलावा जिले के 106 विद्यालय भवन जर्जर अथवा अनुपयोगी घोषित किए जा चुके हैं। विधानसभा में उठे इन मुद्दों ने कबीरधाम जिले में मूलभूत सुविधाओं की वास्तविक स्थिति को उजागर कर दिया है। अब लोगों की नजर सरकार की आगामी कार्ययोजना और इन समस्याओं के समाधान पर टिकी हुई है।

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी नागरिकों की समस्याएं

गरियाबंद। कलेक्टर बीएस उइके ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में जिले के शहरी, ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं, मांगें एवं शिकायतें सुनीं। उन्होंने प्रत्येक आवेदन का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को नियमानुसार एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनदर्शन में कुल 31 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से कुछ प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए। गरियाबंद की बिन्दु सिन्हा ने पेंशन कि राशि दिलाने के संबंध में कलेक्टर बीएस उइके को आवेदन सौपा। इसी तरह ग्राम रजनकट्टा के मोहन लाल सोनी ने न्याय दिलाने के लिए, ग्राम हसौद के राजाराम ने पट्टा प्रदान कराने एवं पीएम आवास सूची में नाम जोड़ने के लिए, ग्राम फुलझर के हेमलाल यादव ने एग्रीस्टेक में पंयीजन कराने के लिए, ग्राम कुटेना के खुबचंद साहू ने आर्थिक सहायता राशि प्रदान कराने के लिए, ग्राम धवलपुरडीह की पायल महिलांग ने आधार कार्ड में त्रुटि सुधार कराने के लिए, ग्राम तूहामेटा के देवराज नेताम ने रोजगार दिलाने के लिए, ग्राम धवलपुर के रावेन्द्र नाथ सोनी ने पट्टा दिलाने के लिए।

संपादकीय

लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई जरूरी..

लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल में बंद रहते हुए भी अपनी आपराधिक योजनाओं को अंजाम दे पाता था, तो उसमें यही पहलू सबसे अहम है कि उसे तकनीकी संसाधन कैसे हासिल हुए और उसे मुहैया कराने तथा आसानी से उसका इस्तेमाल करने की सुविधा उसे किसके संरक्षण में मिलती थी।यह चिंता की बात है कि देश की जेल में बंद होने के बावजूद किसी कैदी पर अपनी आपराधिक गतिविधियां संचालित करने के आरोप लगते हैं और मामला अन्य देशों के दायरे में भी पहुंच जाता है। सरकार को जहां समय रहते इस मसले पर सख्त कदम उठाना चाहिए था, वहां उसने लगातार इस सवाल की अनदेखी की कि जेल में होने के बावजूद कोई कैदी कैसे अपनी मनमानी कर पा रहा है और उसे किसका संरक्षण मिला हुआ है।ऐसे आरोप आम रहे हैं कि कुख्यात अपराधी लारेंस बिश्नोई जेल में बंद होने के बावजूद देश और विदेश में काम कर रहे अपने गिरोह के जरिए हत्या, रंगदारी और फिरौती जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देता रहा है।अब अमेरिका के न्याय विभाग के आरोपपत्र में लारेंस बिश्नोई गिरोह को अभिनेता सलमान खान के घर पर गोलीबारी, पंजाबी अभिनेता और गायक गिप्पी ग्रेवाल को धमकी तथा पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिलाने जैसी कई घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आरोपपत्र में यह भी कहा गया है कि इस संगठित गिरोह के सदस्यों ने अक्सर भारत और विदेश में बसे भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक और राजनीतिक हस्तियों तथा बड़े व्यावसायियों को हिंसा का निशाना बनाया। जाहिर है, लारेंस बिश्नोई की हरकतों के बारे में जितनी भी जानकारी सामने आ सकी है, उस आलोक में अमेरिका के न्याय विभाग के आरोपपत्र में आए तथ्य हैरान नहीं करते हैं। मगर यह समझना मुश्किल है कि वह अपनी आपराधिक योजनाएं बनाने से लेकर उन्हें अंजाम देने तक की सुविधाएं कैसे और किसके जरिए हासिल करता रहा। अब एक अभियान के तहत अमेरिका, कनाडा और स्पेन की कानून प्रवर्तन एजंसियों ने मिल कर जो कार्रवाई की है, उसमें तीन देशों में चौबीस लोगों की गिरफ्तारी की गई और सैंतीस के खिलाफ आरोप तय किए गए। के लिए किसी अन्य देश में आरोपपत्र तय किए जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसी ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई, जिससे जेल में बंद एक कुख्यात कैदी को अपना अपराध-तंत्र संचालित करने से रोका जा सके। बिश्नोई के गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया पर अपना प्रभाव बढ़ाने और भय पैदा करने के लिए खुलेआम धमकी जारी करते थे, तो उनके खिलाफ समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई?गौरतलब है कि कनाडा में एक खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लारेंस बिश्नोई गिरोह पर लगा था और उसी संदर्भ में भारत और कनाडा के बीच गंभीर कूटनीतिक विवाद पैदा हो गया था।

पृथ्वी आज जिस सबसे बड़े पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है, उसमें जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता का क्षरण और प्रदूषण के साथ-साथ प्लास्टिक प्रदूषण भी एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुका है। कभी आधुनिक जीवन की सुविधा और विकास का प्रतीक मानी जाने वाली प्लास्टिक आज मानव सभ्यता के लिए अभिशाप सिद्ध हो रही है। विशेष रूप से सिंगल-यूज प्लास्टिक बैग ने हमारी जीवन-शैली को इतना जकड़ लिया है कि उससे मुक्ति के बिना न स्वच्छ पर्यावरण की कल्पना की जा सकती है और न ही स्वस्थ भविष्य की। इसी चिंता को लेकर प्रतिवर्ष 3 जुलाई को 'अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस' मनाया जाता है। यह केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी का दिन है कि यदि अब भी हमने अपनी आदतें नहीं बदलीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी।

प्लास्टिक बैग से जकड़ी जीवन-शैली से पर्यावरण तबाह

(ललित गर्ग)

आज विश्व में हर वर्ष लगभग 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार इसका एक बड़ा हिस्सा केवल एक बार उपयोग के बाद कचरे में बदल जाता है। अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 1.1 से 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक समुद्रों में पहुँच जाता है।

पृथ्वी आज जिस सबसे बड़े पर्यावरणीय संकट से जूझ रही है, उसमें जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता का क्षरण और प्रदूषण के साथ-साथ प्लास्टिक प्रदूषण भी एक गंभीर वैश्विक चुनौती बन चुका है। कभी आधुनिक जीवन की सुविधा और विकास का प्रतीक मानी जाने वाली प्लास्टिक आज मानव सभ्यता के लिए अभिशाप सिद्ध हो रही है। विशेष रूप से सिंगल-यूज प्लास्टिक बैग ने हमारी जीवन-शैली को इतना जकड़ लिया है कि उससे मुक्ति के बिना न स्वच्छ पर्यावरण की कल्पना की जा सकती है और न ही स्वस्थ भविष्य की। इसी चिंता को लेकर प्रतिवर्ष 3 जुलाई को 'अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस' मनाया जाता है। यह केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी का दिन है कि यदि अब भी हमने अपनी आदतें नहीं बदलीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी।

आज विश्व में हर वर्ष लगभग 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार इसका एक बड़ा हिस्सा केवल एक बार उपयोग के बाद कचरे में बदल जाता है। अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 1.1 से 1.4 करोड़ टन प्लास्टिक समुद्रों में पहुँच जाता है। यदि यही स्थिति बनी रही तो वर्ष 2050 तक समुद्रों में मछलियों से अधिक प्लास्टिक होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। यह केवल एक आँकड़ा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के लिए भयावह भविष्य का संकेत है। सबसे अधिक चिंता का विषय यह है कि प्लास्टिक अब केवल धरती पर बिखरा कचरा नहीं रहा, बल्कि हमारे शरीर का भी हिस्सा बन चुका है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हवा, पानी, भोजन, नमक, दूध, शहद और यहाँ तक कि मानव रक्त, फेफड़ों तथा गर्भनाल में भी माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए जा चुके हैं। एक सामान्य व्यक्ति प्रतिवर्ष हजारों सूक्ष्म प्लास्टिक कण भोजन, पेयजल और साँस के माध्यम से अपने शरीर में पहुँचा रहा है। यह स्थिति कैंसर, हार्मोनल असंतुलन, हृदय रोग, प्रजनन संबंधी समस्याओं और प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव जैसी अनेक स्वास्थ्य चुनौतियों को जन्म दे रही है। आधुनिक जीवनशैली में प्लास्टिक बैग हमारी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। सब्ज़ी और किराने की खरीदारी से लेकर कपड़े, दवाइयाँ, भोजन, ऑनलाइन डिलीवरी, उपहार पैकिंग और घरेलू सामान तक लगभग हर कार्य में प्लास्टिक बैग का उपयोग हो रहा है। सुविधा और सस्तेपन के कारण इनका प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारा जीवन मानो प्लास्टिक की गिरफ्त में आ गया है। एक बार उपयोग के बाद फेंके जाने वाले ये बैग पर्यावरण, जल स्रोतों, वन्यजीवों और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। इसलिए समय की मांग है कि हम कपड़े, जूट या कागज़ के थैलों को अपनाकर प्लास्टिक बैग से मुक्ति का संकल्प लें।

प्लास्टिक केवल मनुष्य के स्वास्थ्य का ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पर्यावरण का भी शत्रु है। यह मिट्टी की उर्वरता को कम करता है, जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, नालियों को जाम कर शहरी बाढ़ का कारण बनता है तथा पशु-पक्षियों और समुद्री जीवों की असमय मृत्यु का कारण बनता है। गायों के पेट से कई-कई किलो प्लास्टिक निकलने की घटनाएँ अब सामान्य हो गई हैं। समुद्री कछुए, डॉल्फिन, व्हेल और पक्षी प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल लेते हैं और धीरे-धीरे मृत्यु का शिकार बन जाते हैं। इस प्रकार प्लास्टिक केवल पर्यावरण नहीं, बल्कि जीवन के पूरे जैविक तंत्र को नष्ट कर रहा है। विडम्बना यह है कि प्लास्टिक का सबसे बड़ा आकर्षण उसकी सुविधा है और यही सुविधा सबसे बड़ा संकट बन गई है। कुछ मिनटों के उपयोग के लिए बना प्लास्टिक बैग सैकड़ों वर्षों तक नष्ट नहीं होता। जिस वस्तु का उपयोग हम कुछ मिनट करते हैं, उसका दुष्प्रभाव कई पीढ़ियाँ भुगतती हैं। सुविधा की यह संस्कृति वास्तव में विनाश की संस्कृति बनती जा रही है।

भारत में भी प्लास्टिक प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है। देश में प्रतिदिन हजारों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसका बड़ा भाग खुले में पड़ा रहता है या नदियों एवं समुद्र तक पहुँच जाता है। विभिन्न राज्यों ने सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, किन्तु प्रतिबंध का प्रभाव तभी दिखाई देगा जब समाज स्वयं इसके प्रति जागरूक होगा। केवल कानून से आदतें नहीं बदलतीं, उसके लिए सामाजिक चेतना आवश्यक होती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस दिशा में अनेक सकारात्मक पहल की हैं। स्वच्छ भारत अभियान, सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व जैसी नीतियाँ महत्त्वपूर्ण कदम हैं। किंतु इनकी सफलता तभी संभव है जब उद्योग, व्यापार, स्थानीय निकाय और आम नागरिक समान रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आज आवश्यकता केवल प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की नहीं, बल्कि जीवनशैली बदलने की है। जब तक हमारी खरीदारी की आदतें नहीं बदलेंगी, तब तक प्लास्टिक का उपयोग कम नहीं होगा। कपड़े या जूट का थैला साथ रखना, पुनः उपयोग योग्य बोतलों और डिब्बों का प्रयोग करना, अनावश्यक पैकेजिंग से बचना तथा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देना-ये छोटे-छोटे कदम बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। उद्योगों की भी बड़ी जिम्मेदारी है। उत्पादों की पैकेजिंग को पर्यावरण-अनुकूल बनाना, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का उपयोग करना और प्लास्टिक कचरे के संग्रह एवं पुनर्चक्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करना समय की माँग है। केवल लाभ कमाने की मानसिकता से प्रकृति का संरक्षण संभव नहीं है। उद्योगों को 'ग्रीन बिजनेस' की दिशा में आगे बढ़ना होगा। शिक्षा संस्थानों की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यदि विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्यावरणीय जीवनशैली को व्यवहार का हिस्सा बनाया जाए, बच्चों को कपड़े के थैले उपयोग करने, प्लास्टिक-मुक्त परिसर बनाने और पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों से जोड़ा जाए, तो आने वाली पीढ़ियाँ अधिक संवेदनशील बनेंगी। पर्यावरण शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक का विषय नहीं, बल्कि जीवन का संस्कार बननी चाहिए।

आज पूरी दुनिया 'सर्कुलर इकोनॉमी' की ओर बढ़ रही है, जहाँ उत्पादों का पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और संसाधनों का न्यूनतम दोहन प्रमुख लक्ष्य है। भारत के लिए भी यही भविष्य का मार्ग है। यदि हम पारंपरिक भारतीय जीवन-पद्धति को देखें तो वहाँ कपड़े के झोले, मिट्टी के बर्तन, धातु के पात्र और प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग सामान्य जीवन का हिस्सा थे। आधुनिकता के नाम पर हमने इन्हें छोड़ दिया और प्लास्टिक को अपना लिया। अब समय आ गया है कि आधुनिक विज्ञान और भारतीय परंपरा का समन्वय करते हुए टिकाऊ जीवनशैली अपनाई जाए। यह भी समझना होगा कि प्लास्टिक प्रदूषण केवल सरकार का विषय नहीं है। यह प्रत्येक नागरिक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले ले कि वह प्लास्टिक बैग स्वीकार नहीं करेगा, उसी दिन इस समस्या का बड़ा समाधान प्रारम्भ हो जाएगा। बाजार वही वस्तु देता है जिसकी माँग होती है। यदि माँग समाप्त होगी तो आपूर्ति भी स्वतः कम हो जाएगी।

अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हमें केवल प्लास्टिक छोड़ने का संदेश नहीं देता, बल्कि यह प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को पुनर्जीवित करने का अवसर भी है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी हमारे पूर्वजों की विरासत नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। यदि हम इसे सुरक्षित नहीं रख पाए तो विकास के सारे दावे अर्थहीन हो जाएँगे। महात्मा गांधी ने कहा था-''प्रकृति प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक के लालच को नहीं।'' आज यह कथन पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। प्लास्टिक का अनियंत्रित उपयोग हमारी आवश्यकताओं का नहीं, बल्कि उपभोक्तावादी लालच का परिणाम है।

आइए इस 3 जुलाई को केवल एक दिवस न मानें, बल्कि एक जन-आंदोलन का प्रारंभ करें। अपने घर, परिवार, विद्यालय, कार्यालय और बाजार से प्लास्टिक बैग को विदा करने का संकल्प लें। कपड़े का थैला हमारी पहचान बने, पर्यावरण हमारी प्राथमिकता बने और स्वच्छ पृथ्वी हमारी विरासत बने। जब प्लास्टिक का उपयोग घटेगा, तभी प्रकृति मुस्कुराएगी, जब प्रकृति मुस्कुराएगी, तभी मानवता का भविष्य सुरक्षित होगा। यही अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस का वास्तविक संदेश है और यही हमारे समय का सबसे बड़ा पर्यावरणीय धर्म भी।लेखक, पत्रकार एवं स्तंभकार है।

एक मासूम, कई हैवान, हमारी सामूहिक खामोशी

(तवलीन सिंह)

यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि हमारे समय का सबसे शर्मनाक सच है, जहां राजनीति, प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

राजस्थान की बच्ची से जुड़े जघन्य अपराध के बहाने यह लेख समाज, राजनीति और न्याय व्यवस्था की सामूहिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाता है। राजस्थान की एक बेटी की कहानी सुनकर पिछले सप्ताह मुझे दुख और गुस्से से ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। कैसा देश है हमारा कि एक बच्ची के साथ बत्तीस दरिंदों ने पांच दिनों तक बलात्कार किया और किसी को पता तक नहीं लगा। बच्ची को एक होटल से दूसरे होटल में ले जाया जाता था, फिर भी न शहर के शासकों को खबर हुई और न पुलिस को।

कैसे? क्यों? बच्ची को आटो चालक ने अगवा करके किसी होटल मालिक को बेचा। उसने आगे कई और होटल मालिकों के हवाले बच्ची को किया और इंटरनेट पर उसकी फोटो डाल कर दरिंदों को आमंत्रित किया।

किसी तरह जब वह इस नरक से जान बचा कर भागी, तो उसका इतना बुरा हाल हो चुका था कि उसकी जान अस्पताल में भी कोई नहीं बचा सका। दरिंदों को पकड़ कर रस्सियों से बांध कर शहर की सड़कों पर पिटवाने की घटना तो चर्चा का विषय बनी, लेकिन आगे क्या होगा वह भी सुन लीजिए। उनको जेल भेजा जाएगा जरूर और जिनकी थोड़ी बहुत पहुंच है, उनकी जमानत भी शायद हो जाएगी।

जम्मू के ब्लात्कारियों का क्या हुआ किसी को नहीं पता- उसके बाद कई साल उन पर मुकदमा चलेगा। इतने साल गुजर जाएंगे कि दुनिया भूल जाएगी कि उनका अपराध क्या था। क्या आप जानते हैं कि उस बच्ची के बलात्कारियों के साथ क्या हुआ था, जिन्होंने उस मासूम को जम्मू के एक मंदिर में बेहोश कर उससे बलात्कार किया था और जब मरने वाली थी, तो उसे मार डाला उसका सिर फोड़ कर? दंडित हुए भी हैं क्या? कोई नहीं जानता, क्योंकि उस बच्ची की कहानी हम बहुत पहले भूल चुके हैं।

राजस्थान की इस बच्ची की कहानी सुन कर कई नेता-अभिनेता दुख व्यक्त कर चुके हैं सोशल मीडिया पर, बिल्कुल वैसे जैसे जम्मू की उस छोटी-सी बच्ची की कहानी सुन कर हुआ था। दुख व्यक्त करने वाले हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इस किस्म के घिनौने अपराधों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए बहुत कम लोग सामने आते हैं।

क्यों नहीं दुख व्यक्त करने वाले ये लोग दबाव डालते हैं हमारे शासकों पर कि जब बच्चियों के साथ ऐसा होता है, तो खास अदालतों में मुकदमा चलना चाहिए, ताकि दशकों तक मुकदमा चलता न रहे? क्यों नहीं ऊंची आवाज में कहते हैं कि भारत का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए कि रोज इस देश में बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। हर साल 31 हजार मामले दर्ज होते हैं, लेकिन जब अदालतों तक बात पहुंचती है, तो केवल 30 फीसद बलात्कारी दंडित होते हैं।

ऐसा क्यों है? यह सवाल हमको बार-बार पूछना चाहिए अपने राजनेताओं से, लेकिन हम इसलिए पूछते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इन लोगों को ऐसी बातों की कोई परवाह नहीं है। उनका ध्यान रहता है बड़ी-बड़ी चीजों पर जैसे कि संसद में महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षित करना। जैसे महिलाओं के वोट बटोरने के लिए उनको हर महीने पंद्रह सौ से दो हजार रुपए दिलवाना, जैसे शहर की बसों में उनके लिए मुफ्त यात्रा का इंतजाम करना, लेकिन जब हमारे देश में किसी शर्मनाक घटना के बारे में जानकारी मिलती है, तो हमारे नेता अपने बिलों में घुस जाते हैं, ताकि उनके पास कोई शिकायत लेकर न आए।

लोकसभा के अंदर कुछ महिला सांसद हैं जो आवाज उठाती हैं जब कोई बहुत ही शर्मनाक घटना घटती है, लेकिन उसके बाद कभी नहीं मालूम करने की कोशिश करती हैं कि न्याय हुआ है उस बच्ची के साथ या नहीं? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। नारा अच्छा है, बहुत अच्छा है।

राजस्थान के सीएम ने कोई आवाज नहीं उठाई- अपने प्रधानमंत्री ने एक अरसा पहले यह नारा देश की बेटियों को दिया था और कई कोशिशें अपनी तरफ से की थीं यह साबित करने के लिए कि उनके दिल में देश की बेटियों के लिए कितना प्यार है, लेकिन वास्तव में प्यार जताना होता, तो प्रधानमंत्री ऐसी घटनाओं के खिलाफ अपनी आवाज तो कम से कम उठाते। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए इतना तो हो सकता है न कि मुख्यमंत्री अपनी आवाज उठाएं। सच यह है कि बलात्कार भी राजनीतिक लिबास पहने हुए है। जब कोई घटना घटती है किसी कांग्रेस शासित राज्य में, तो भाजपाई खूब हल्ला मचाते हैं और जब भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं होती हैं, तो हल्ला बोलते हैं कांग्रेस के लोग। इन नेताओं के आंसू घड़ियाली न होते, तो देश की बेटियों की किस्मत इतनी बुरी न होती। दरिंदों को रोकना है, तो सामाजिक स्तर पर काम होना जरूरी है और कानूनी स्तर पर भी। ये सारी चीजें तब होने लगेंगी, जब राजनेता नेतृत्व दिखाएंगे।

सिद्धान्तविहीन राजनीति का बदलता चेहरा

(डा. रवीन्द्र अरजरिया)

बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल यानी लाल-बाल-पाल जैसे नेताओं ने इसे ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ सीधे संघर्ष का रूप दे दिया। सन् 1907 के सूरत अधिवेशन में पार्टी की नीतियों के कारण उसका विभाजन गरम दल और नरम दल के रूप में हो गया। एक घटक ने आजाद हिन्द फौज बनाई तो दूसरे ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। सन् 1920 में नागपुर अधिवेशन आयोजित किया गया। मोहनदास कर्मचन्द गांधी के आगमन के साथ कांग्रेस का चरित्र पूरी तरह बदल गया। पार्टी के संविधान में परिवर्तन किये गये। परिवर्तनों का यह क्रम आज तक चल रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को कलकत्ता में जन्मे डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की थी।

देश में राजनैतिक बिसात पर नित नये पैतरे देखने को मिल रहे हैं। स्वार्थवादी सिद्धान्तों ने संचयकारी सोच के साथ मिलकर आदर्शवादी मूल्यों को तिलांजलि देना शुरू कर दिया है। पार्टियों के मूल उद्देश्य किस्तों में कत्ल किया जा रहे है। दल-बदल से लेकर संगठनों के जोड-तोड तक की घटनायें सामने आ रहीं हैं। ऐसे में राजनैतिक दलों की स्थापनाओं और उनके उद्देश्यों के प्रकाश में वर्तमान की समीक्षा अतिआवश्यक हो जाती है। स्काटलैण्ड के मोंट्रोस शहर में जन्मे ब्रिटिश अफसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों के शिक्षित और बुद्धिजीवी भारतीयों को एक साझा राजनीतिक मंच प्रदान करना था ताकि भारतीयों की समस्याओं, शिकायतों और मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष संवैधानिक ढंग से रखा जा सके लेकिन सन् 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान पार्टी एक जन-आंदोलन में बदलने लगी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल यानी लाल-बाल-पाल जैसे नेताओं ने इसे ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ सीधे संघर्ष का रूप दे दिया। सन् 1907 के सूरत अधिवेशन में पार्टी की नीतियों के कारण उसका विभाजन गरम दल और नरम दल के रूप में हो गया। एक घटक ने आजाद हिन्द फौज बनाई तो दूसरे ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया। सन् 1920 में नागपुर अधिवेशन आयोजित किया गया। मोहनदास कर्मचन्द गांधी के आगमन के साथ कांग्रेस का चरित्र पूरी तरह बदल गया। पार्टी के संविधान में परिवर्तन किये गये। परिवर्तनों का यह क्रम आज तक चल रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को कलकत्ता में जन्मे डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में एक राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की थी। इस दल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वैचारिक समर्थन प्राप्त था। कांग्रेसी प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी के द्वारा सन् 1975 से 1977 कर आपातकाल लगा कर कथित तौर पर मनमानी, तानाशाही और गुण्डागिरी की गई। इसके विरोध स्वरूप सत्ताधारी कांग्रेस के विरोध में सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने एकजुट होकर बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में जन्मे जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में सन् 1977 में जनता पार्टी का गठन किया गया जिसमें जनसंघ का भी विलय हो गया, परन्तु सन् 1980 में जनता पार्टी के भीतर दोहरी सदस्यता के विवाद और वर्चस्व की लड़ाई के कारण एक बडे घटक ने अटल बिहारी वाजपेई तथा लाल कृष्ण आडवारी के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन कर लिया। पार्टी का उद्देश्य एकात्म मानववाद पर आधारित भारत को एक सशक्त, आत्मनिर्भर, और समृद्ध राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करना था। वहीं पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित अरबालिया गांव में जन्मे नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जिन्हें मानवेन्द्र नाथ राय भी कहा जाता है, ने उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को समाप्त करके वर्गहीन और शोषण-मुक्त साम्यवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से 17 अक्टूबर 1920 को तत्कालीन सोवियत संघ के ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। उसके बाद 26 दिसंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में मानवेंद्र नाथ रॉय ने अपनी पत्नी इवलिन ट्रेंट रॉय और अबानी मुखर्जी के साथ मिलकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। महाराष्ट्र के पूना नगर में जन्मे बाल केशव ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना 19 जून 1966 को मुंबई में मराठी मानुष और स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य की थी जो बाद में कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा वाली एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के रूप में विकसित हुई। राम मंदिर आन्दोलन से लेकर सनातन के विभिन्न आन्दोलनों में शिवसेना ने अहम भूमिका का निर्वहन किया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गाँव में जन्मे मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 को डाक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर आधारित समानता की परिकल्पना को साकार करने हेतु की थी ताकि आर्थिक और सामाजिक समानता के सिद्धांतों की व्यवहारिक परिणति की जा सके। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना पंजाब के रूपनगर यानी रोपण जिले के खवासपुर यानी पिरथीपुर बुंगा गांव में जन्मे कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को अंबेडकर जयंती के दिन की थी जिसका उद्देश्य डाक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फुले तथा पेरियार के सिद्धान्तों के आधार पर कथित मनुवादी व्यवस्था को उखाडना था। पार्टी के संस्थापक का मानना था कि राजनीतिक सत्ता सभी समस्याओं की चाबी होती है। इसी तरह अनेक पार्टियों ने स्थापना काल में अनेक सकारात्मक उद्देश्यों का शंखनाद किया था। कहीं जातिगत हितों को साधने का मुद्दे रेखांकित किये गये तो कहीं भाषागत विभेद की खाई बढाने की कोशिशें हुईं। इन प्रयासों ने राजनैतिक रंग लेकर सत्ता सुख की कल्पनाओं को पंख देना शुरू कर दिये। वर्तमान में लगभग सभी पार्टियां अपने मूल सिद्धान्तों, आदर्शों और नीतियों को तिलांजलि देकर केवल और केवल स्वार्थ सिद्धि के प्रयासों में लगी हैं। चुनावी जंग से लेकर सिंहासन तक पहुंचने के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद आजमाये जा रहे हैं। वर्तमान उप चुनाव में मध्य प्रदेश का दतिया और बिहार का बांकीपुर का टिकिट वितरण इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। पार्टियों के लिए समर्पण, त्याग और सेवा के मूल्य समाप्त हो चुके हैं। चाटुकारिता, निजी हित और वैभव संकलन की संभावनायें ही योग्यता के नये मापदण्ड बन गये हैं। सिद्धान्तविहीन राजनीति का बदलता चेहरा किसी भी दशा में राष्ट्रहित की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। ऐसे में आम आवाम की राय कायम करने में वर्तमान कार्य, राष्ट्रीय प्रगति और समस्याओं से निजात पाने वाले कारक ही उत्तरदायी होंगे। इस बार बस इतना ही। अगले सप्ताह एक नई आहट के साथ फिर मुलाकात होगी।

संक्षिप्त समाचार

दो नाबालिग लड़कियों के अपहरण से लेकर मारपीट और अवैध हथियार तक के मामले

रायपुर। राजधानी रायपुर में बीते 24 घंटे के दौरान कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मामलों में पुलिस ने 17 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें दो नाबालिग लड़कियों के कथित अपहरण, मारपीट, सड़क दुर्घटना, अवैध हथियार रखने और घर में घुसकर हमला करने जैसी घटनाएं शामिल हैं। खमतराई और टिकरापारा थाना क्षेत्र में दो किशोरियों के लापता होने के बाद जांच के दौरान भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत अपहरण के मामले दर्ज किए गए हैं। खमतराई में 15 वर्षीय और टिकरापारा में 17 वर्षीय किशोरी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है। पुरानी बस्ती, गुढ़ियारी, राजेंद्र नगर, कोतवाली, टिकरापारा, तेलीबांधा और देवेंद्र नगर थाना क्षेत्रों में पुरानी रंजिश, विवाद और गाली-गलौज के बाद मारपीट की कई घटनाएं सामने आईं। इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ जान से मारने की धमकी, मारपीट और अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किए गए हैं। टिकरापारा थाना क्षेत्र के काली नगर लालपुर में आरोपियों पर घर में घुसकर मारपीट करने और ओप्पो कंपनी का मोबाइल अपने कब्जे में लेने का मामला दर्ज किया गया है। सरस्वती नगर, तेलीबांधा और टिकरापारा थाना क्षेत्रों में तेज एवं लापरवाही से वाहन चलाने के तीन मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें एक बस द्वारा मकान की सीमेंट शीट क्षतिग्रस्त करने तथा दो अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में वाहन क्षतिग्रस्त होने और लोगों के घायल होने की शिकायतें शामिल हैं।

हिस्ट्रीशीटर की हत्या से फैली सनसनी, जेल से छूटने के कुछ दिन बाद पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रविवार देर रात एक हिस्ट्रीशीटर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के कुंदरापारा में हुई इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान लेखराम कोठारी के रूप में हुई है, जो पद्मनाभपुर थाना का हिस्ट्रीशीटर था। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रविवार रात कुछ लोगों ने उस पर हमला कर लाठी-डंडों और अन्य हथियारों से बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पद्मनाभपुर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, लेखराम कोठारी को हाल ही में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल से रिहा होने के बाद वह वापस इलाके में आया था। इसी बीच रविवार रात उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी: दो बाइक, सोने के जेवर समेत नगदी रकम पार

रायपुर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित सीएसईबी चैकी अंतर्गत एक सूने मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर दो दोपहिया वाहन, सोने के जेवर और नगदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मकान मालिक अपने घर में ताला लगाकर गांव गई हुई थी। घर की देखरेख के लिए उसने अपनी दोस्त अंजली सिंह को चाबी सौंप रखी थी। इसी दौरान उसके भाई और माता-पिता भी बिहार के औरंगाबाद जिले स्थित अपने पैतृक गांव गए हुए थे। शिकायतकर्ता जब पटना जंक्शन पर थी, तभी अंजली सिंह ने फोन कर घर में चोरी होने की सूचना दी। कोरबा लौटने पर शिकायतकर्ता ने देखा कि मुख्य दरवाजे और कमरों के ताले टूटे हुए थे। अलमारी का लॉक भी टूटा मिला और घर का सामान बिखरा पड़ा था। इससे साफ था कि चोरों ने पूरे घर की तलाशी लेकर कीमती सामान समेट लिया। चोर घर से एक हीरो स्प्लेंडर (सीजी 12 बी डब्ल्यू 2329) और एक होंडा एक्टिवा (सीजी 12 बीआर 4289) चोरी कर ले गए। दोनों वाहनों की अनुमानित कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई गई है। इसके अलावा अलमारी में रखी एक जोड़ी सोने की बालियां, एक सोने की चेन तथा नगदी भी चोरी हो गई। नगदी और जेवरों की कुल कीमत का आकलन परिजनों के लौटने के बाद किया जाएगा।

पुलिस ने चोरी के दो मामलों का किया खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन बाज' के तहत थाना चिल्फी पुलिस ने संपत्ति संबंधी चोरी के दो अलग-अलग मामलों का त्वरित खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 60 हजार रुपये नकद, चोरी किया गया सबमर्सिबल मोटर पंप और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की है।

गनियारी में आयोजित दशगात्र एवं श्रद्धांजलि सभा में हुए शामिल

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पद्म विभूषण स्व. डॉ. तीजन बाई को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

■ लोककला की महान साधिका डॉ. तीजन बाई की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाएगी राज्य सरकार : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय दुर्ग जिले के ग्राम गनियारी पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविख्यात पंडवानी गायिका, पद्मश्री, पद्मभूषण एवं पद्म विभूषण से सम्मानित स्वर्गीय डॉ. तीजन बाई के दशगात्र एवं श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके पैतृक गृह ग्राम गनियारी में आयोजित इस शोकसभा में मुख्यमंत्री ने स्व. डॉ. तीजन बाई के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें सादर नमन किया तथा शोकसंतप्त परिजनों से भेंट कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर स्व. डॉ. तीजन बाई के पुत्र श्री दिलहरण पारधी तथा परिवार के अन्य सदस्यों से भेंट कर उनका हालचाल जाना और उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्व. डॉ. तीजन बाई केवल छत्तीसगढ़ की नहीं, बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक पहचान थीं। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा, अद्भुत साधना और पंडवानी की कापालिक शैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि स्व. डॉ. तीजन बाई का योगदान आने वाली पीढ़ियों को भी निरंतर प्रेरित करता रहेगा। स्व. डॉ. तीजन बाई का संपूर्ण जीवन लोककला, संस्कृति और परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन को समर्पित रहा। उन्होंने पंडवानी को विश्व मंच तक पहुंचाकर न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि भारतीय लोक संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाई। उनकी कला, साधना और सांस्कृतिक विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्योत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष 'डॉ. तीजन बाई लोककला अलंकरण' प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम गनियारी स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का नामकरण स्व. डॉ. तीजन बाई के नाम पर किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र के विद्यार्थी उनके जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि लोककला की महान साधिका डॉ. तीजन बाई की स्मृतियों को राज्य सरकार द्वारा चिरस्थायी रखते हुए उनकी जीवनभर की कला-साधना के प्रतीक रहे तंबूरे को रायपुर के संग्रहालय में पूरे सम्मान के साथ संरक्षित रखा जाएगा, जिससे भविष्य की पीढ़ियां उनकी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकें। श्रद्धांजलि सभा को सांसद श्री विजय बघेल, प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री राजेश अग्रवाल तथा विधायक पद्मश्री श्री अनुज शर्मा ने भी संबोधित किया। उन्होंने स्व. डॉ. तीजन बाई के व्यक्तित्व, कृतित्व और लोककला के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की तथा उन्हें सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पित की।

पुलिया निर्माण से धनगोल को मिली नई जिंदगी.....

■ मनरेगा और विशेष केंद्रीय सहायता के अभिसरण से बनी 6 मीटर पुलिया, वर्षभर निर्बाध आवागमन हुआ संभव

रायपुर। संवाददाता

ग्राम पंचायत अंगमपल्ली के आश्रित ग्राम धनगोल में वर्षों से चली आ रही आवागमन की समस्या अब अतीत बन गई है। मनरेगा एवं विशेष केंद्रीय सहायता के अभिसरण से निर्मित 6 मीटर लंबी पुलिया ने ग्रामीणों के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है। अब बारिश के मौसम में भी गाँव का मुख्यालय से संपर्क बना रहता है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और दैनिक आवागमन की सुविधाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक सुगम हो गई हैं।धनगोल के ग्रामीण लंबे समय से वर्षा ऋतु में मार्ग पर पानी भर जाने के कारण भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। बरसात के दौरान गाँव का संपर्क मुख्यालय से पूरी तरह कट जाता था, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई, किसानों की कृषि गतिविधियाँ, मरीजों को समय पर उपचार तथा ग्रामीणों की दैनिक जरूरतें गंभीर रूप से प्रभावित होती थीं।ग्रामीणों की इस समस्या का स्थायी समाधान करते हुए मनरेगा एवं विशेष केंद्रीय सहायता (स्ट्र) के अभिसरण से धनगोल मार्ग पर 6 मीटर पुलिया का निर्माण कराया गया। इस परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 17.63 लाख रुपये रही, जिसमें मनरेगा से 7.63 लाख रुपये तथा स्ट्र से 10 लाख रुपये का योगदान दिया गया। निर्माण कार्य का शुभारंभ 2 जनवरी 2026 को हुआ।यह परियोजना केवल आधारभूत अधोसंरचना के विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि निर्माण अवधि के दौरान स्थानीय रोजगार सृजन का भी महत्वपूर्ण माध्यम बनी।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अभिनव पवेलियन को मिला राष्ट्रीय सम्मान

रायपुर। संवाददाता

ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (टीटीएफ) कोलकाता-2026 में छत्तीसगढ़ पर्यटन ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तीन दिवसीय इस प्रतिष्ठित पर्यटन आयोजन के सफल समापन पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड को देश के 21 राज्यों की सहभागिता के बीच उसके आकर्षक, सृजनात्मक एवं प्रभावशाली पवेलियन के लिए बेस्ट डेकोरेशन ऑफ स्टॉल एंड अपीयरेंस सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जनजातीय जीवन, प्राकृतिक पर्यटन, धार्मिक धरोहरों और आधुनिक पर्यटन दृष्टिकोण को राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के सफल प्रयासों की महत्वपूर्ण पहचान है। 10 से 12 जुलाई तक कोलकाता के विश्व बंगला प्रांगण में आयोजित देश के प्रतिष्ठित पर्यटन व्यापार मेले में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड का पवेलियन तीनों दिनों तक आगंतुकों, पर्यटन विशेषज्ञों, टूर ऑपरेटर्स और निवेशकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहा। बस्तर की जनजातीय संस्कृति, चित्रकोट एवं तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर, भोरमदेव, धार्मिक एवं इको-टूरिज्म, पर्यटन रिसॉर्ट्स तथा राज्य के विविध पर्यटन परिपथों को आधुनिक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, जिसे व्यापक सराहना मिली। आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा, पर्यटन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के सचिव एस भारतीदासन तथा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसियों, होटल समूहों, पर्यटन विशेषज्ञों और निवेशकों के साथ अनेक महत्वपूर्ण बी-टू-बी बैठकों में सहभागिता की।

24 घंटे में दिव्यांग तक पहुंची ट्राइसाइकिल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशीलता से बदली गणेश राम की जिंदगी

सेवा सेतु बना नागरिकों के लिए भरोसेमंद माध्यम

चार दिन में जारी हुआ आय प्रमाण पत्र,समय सेवाओं का मिला लाभ..

रायपुर/ संवाददाता

शासन द्वारा नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित सेवा सेतु आमजन के लिए सुविधाजनक माध्यम बनता जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों के डिजिटल सत्यापन एवं निर्धारित समय-सीमा में प्रमाण पत्र जारी होने से नागरिकों का समय और श्रम दोनों बच रहे हैं। इसी क्रम में रायगढ़ जिले के ग्राम कोसमपाली निवासी पंकज कुमार विश्वाल का आय प्रमाण पत्र सेवा सेतु के माध्यम से निर्धारित समयावधि में जारी किया गया।

पंकज कुमार विश्वाल के पिता नवीन कुमार विश्वाल ने 5 जुलाई 2026 को लोकसेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन किया गया। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत 9 जुलाई 2026 को तहसीलदार, रायगढ़ द्वारा आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। नवीन कुमार विश्वाल ने बताया कि सेवा सेतु के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान रही। आवेदन जमा करने के बाद तय समय-सीमा के भीतर प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। इससे उन्हें किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और बार-बार कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि आय प्रमाण पत्र समय पर मिलने से बच्चे के शैक्षणिक कार्यों सहित अन्य आवश्यक शासकीय प्रक्रियाओं में सुविधा मिलेगी।

कैंसर मुक्त भविष्य की ओर कदमः धमतरी में विशेष एचपीव्ही टीकाकरण सप्ताह शुरू

रायपुर। धमतरी जिले में बेटियों को सर्वाइकल (गर्भाशय ग्रीवा) कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। जिले में आज से 18 जुलाई 2026 तक विशेष एचपीवी टीकाकरण सप्ताह का आगाज हो गया है। इस महाअभियान के तहत 14 वर्ष की आयु की सभी पात्र बालिकाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नि:शुल्क जीवनरक्षक एचपीव्ही टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए स्कूलों से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों तक व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अभियान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण ही सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि समय पर लगाया गया एचपीव्ही टीका इस गंभीर कैंसर से बचाव का सबसे सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित माध्यम है। यह टीका भविष्य में कैंसर के जोखिम को लगभग समाप्त कर देता है, इसलिए सभी पात्र बालिकाओं का टीकाकरण बेहद जरूरी है। अभियान को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग मिलकर काम कर रहे हैं।

डीआरआई ने पूरे भारत में कई वन्य जीव तस्करी का किया भंडाफोड़

रायपुर। संवाददाता

खुफिया जानकारी के आधार पर गैर-कानूनी वन्यजीव तस्करी के खिलाफ पूरे देश में चलाए गए अभियानों की एक श्रृंखला में, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने देश भर में समन्वित अभियानों के दौरान 440 लुप्तप्राय/संरक्षित वन्यजीवों और लगभग 15 किलोग्राम हाथीदांत की वस्तुओं और हाथीदांत को जब्त किया है; और वन्यजीव तस्करी में शामिल 33 लोगों को गिरफ्तार किया है। 10.07.26 को, डीआरआई के अधिकारियों ने राजस्थान के सुजानगढ़ के पास हाथीदांत के गैर-कानूनी व्यापार में शामिल लोगों को पकड़ा। इस अभियान के परिणामस्वरूप लगभग 11 किलोग्राम हाथीदांत बरामद और जब्त किया गया। चार लोगों को पकड़ा गया और जब्त किए गए हाथीदांत के साथ वन विभाग को सौंप दिया गया, ताकि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत आगे की कार्रवाई की जा सके। भारतीय हाथी (एलीफस मैक्सिमस) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची ढ्ढ के तहत सूचीबद्ध है, जो हाथियों और उनसे प्राप्त उत्पादों के व्यापार पर रोक लगाता है। सीआईटीईएस के तहत अपनी बाध्यताओं के अनुरूप भारत में हाथीदांत का व्यावसायिक व्यापार भी प्रतिबंधित है।

सौर ऊर्जा से रोशन हुआ देवेंद्र का घर

बिजली बिल की चिंता से मिली हमेशा के लिए मुक्ति

■ दंतेवाड़ा के देवेंद्र झाड़ी बने दूसरों के लिए प्रेरणा, 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' से बदली जिंदगी

रायपुर/ संवाददाता

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर भारी-भरकम बिजली बिल से हमेशा के लिए मुक्ति पाई जा सकती है। भारत सरकार 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर सिस्टम पर 78 हजार रूपए तक की सब्सिडी देती है। 1 किलोवाट के लिए 30 हजार रूपए, 2 किलोवाट के लिए 60 हजार रूपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए 78 हजार रूपए तक की वित्तीय सहायता सीधे आपके बैंक खाते में प्रदान की जाती है। दंतेवाड़ा जिले के रहने वाले देवेंद्र झाड़ी के लिए अब हर महीने आने वाला बिजली का बिल कोई चिंता का विषय नहीं रहा। कुछ समय पहले तक वे भी महंगे बिजली बिलों से परेशान रहते थे, लेकिन आज उनके घर की छत पर लगे सोलर पैनल उनके परिवार के लिए बचत और खुशहाली की नई किरण लेकर आए हैं। यह सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए। देवेंद्र ने इस जन-कल्याणकारी योजना का लाभ उठाकर अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित करवाया। इस प्लांट को लगाने के लिए उन्हें केंद्र और राज्य सरकार, दोनों की ओर से बेहतरीन सब्सिडी (वित्तीय सहायता) मिली। सब्सिडी मिलने के कारण सोलर प्लांट लगाने का शुरुआती खर्च

बहुत कम हो गया, जिससे देवेंद्र के लिए इसे लगवाना बेहद आसान हो गया। अपने अनुभव को साझा करते हुए देवेंद्र झाड़ी बेहद खुश नजर आते हैं। वे बताते हैं कि पहले हर महीने बिजली का बिल काफी अधिक आता था, जिससे घर का बजट प्रभावित होता था। लेकिन जब से सोलर पैनल लगा है, बिजली का खर्च न के बराबर हो गया है। अब हमारे घर के पंखे, लाइट और अन्य उपकरण सौर ऊर्जा से ही चलते हैं। इससे हमें बहुत बड़ी आर्थिक राहत मिली है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर घर को आत्मनिर्भर बनाना और नागरिकों को महंगे बिजली बिलों से राहत दिलाना है। 3 किलोवाट तक के घरेलू सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाती है। यह स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देता है, जिससे प्रदूषण कम होता है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। कोई भी इच्छुक नागरिक योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और सरकार द्वारा अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से सुरक्षित तरीके से प्लांट लगवा सकता है। देवेंद्र झाड़ी आज अपने पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। वे दूसरों को भी इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं कि अगर आपके घर की छत पर खाली जगह उपलब्ध है, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं। इससे न सिर्फ आपके पैसों की बचत होगी।

संक्षिप्त समाचार

विधानसभा में गूंजा छत्तीसगढ़ की धरोहरों का मुद्दा, चोरी हुई 19 करोड़ की मूर्ति और दीमक खाए रजिस्टर पर सरकार घिरी

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र मेंसांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण का मुद्दा जोरदार ढंग से उठा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धर्मजीत सिंह ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से जवाब मांगा और राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। अजय चंद्राकर ने कहा कि राज्य गठन के 26 वर्ष बाद भी छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्थित अभिलेखागार तैयार नहीं हो पाया है। उन्होंने सिरपुर, भोरमदेव, राजिम, बारसूर सहित कई ऐतिहासिक स्थलों का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां से प्राप्त प्राचीन मूर्तियों और अवशेषों का समुचित दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है। उन्होंने महंत घासीदास संग्रहालय से 1980 के दशक में चोरी हुई 7वीं शताब्दी की भगवान अवलोकितेश्वर की करीब 19 करोड़ रुपये मूल्य की दुर्लभ प्रतिमा का मामला भी उठाया। चंद्राकर ने कहा कि यह प्रतिमा अमेरिका में बरामद होने के बावजूद राज्य के पास उसके मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि संग्रहालय का रजिस्टर दीमक से नष्ट हो गया। इससे प्रतिमा की वापसी की प्रक्रिया प्रभावित हुई और विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए। भाजपा विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश की कई पुरातात्विक साइटें उपेक्षा का शिकार हैं, केवल एक स्थान पर खुदाई का कार्य चल रहा है। उन्होंने पुरखौती मुक्तांगन की भूमि अन्य कार्यों के लिए आवंटित किए जाने और संस्कृति, इतिहास तथा पुरातत्व पर पर्याप्त शोध नहीं होने का भी मुद्दा उठाया। विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि ताला, मल्हार, बिलासपुर और भोरमदेव जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर भी आधुनिक संग्रहालयों का अभाव है। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सरगुजा के रामगढ़ स्थित प्राचीन नाट्यशाला के संरक्षण पर चिंता जताई। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि राज्य की प्राचीन धरोहरों का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के सहयोग से किया जा रहा है।

सार्वजनिक स्थान पर चाकू लेकर लोगों को धमका रहा बदमाश गिरफ्तार

रायपुर। जिले के बसंतपुर थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धारदार चाकू लेकर लोगों में दहशत फैला रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लोहे का धारदार चाकू बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान तुलाराम सोनकर (37 वर्ष), निवासी सोनकरपारा, नंदई चौक, थाना बसंतपुर के रूप में हुई है। आरोपी के विरुद्ध पूर्व से मारपीट का मामला भी दर्ज है।पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के निर्देशन में जिले में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बसंतपुर पुलिस को सूचना मिली कि नंदई चौक स्थित सार्वजनिक स्थान पर एक व्यक्ति धारदार चाकू लेकर लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक धारदार लोहे का चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 323/2026 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 में मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद जेल वारंट मिलने पर आरोपी को जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक नरेश सार्वा, सहायक उपनिरीक्षक मनमोहन साहू, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक हीरामणी चन्द्रा, आरक्षक चन्द्रशेखर श्रीवास, लक्ष्मण नेताम तथा महिला आरक्षक अनुपमा चन्द्रवंशी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में असामाजिक और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

बोरियाखुर्द की नाइस बेकरी में गंदगी मिलने पर 5 हजार का ई-जुर्माना

रायपुर। राजधानी रायपुर में स्वच्छता संबंधी शिकायत पर नगर निगम जोन-10 की स्वास्थ्य विभाग टीम ने बोरियाखुर्द स्थित नाइस बेकरी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बेकरी में गंदगी और निर्धारित स्वच्छता मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संचालक पर 5 हजार रुपये का ई-जुर्माना लगाया गया। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश तथा जोन-10 के जोन कमिश्नर मोनेश्वर शर्मा के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वार्ड क्रमांक-54 स्थित बोरियाखुर्द में कार्रवाई की। यह निरीक्षण स्वच्छता से संबंधित प्राप्त जनशिकायत के सत्यापन के लिए किया गया था। निरीक्षण के दौरान परिसर में गंदगी फैली हुई मिली और प्रचलित स्वच्छता मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। शिकायत सही पाए जाने पर जोन स्वास्थ्य अधिकारी अमित बेहरा एवं स्वच्छता निरीक्षक यशवंत बेरिहा की मौजूदगी में बेकरी संचालक को भविष्य में स्वच्छता नियमों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी गई। इसके साथ ही नगर निगम ने तत्काल ?5,000 का ई-जुर्माना वसूलते हुए स्पष्ट किया कि शहर में स्वच्छता मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। निगम की टीम ने बताया कि जनशिकायतों का त्वरित निराकरण करते हुए स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।

वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने 65 किसानों को कृषि यंत्र वितरित

रायपुर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर में फार्मर फर्स्ट कार्यक्रमके अंतर्गत मंगलवार को किसान वैज्ञानिक संवाद सह कृषि यंत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के नव-चयनित पांच गांव—बरौंडा, अड़सेना, मोहदी, गनियारी और असौंदा—के किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक खेती, कृषि यंत्रीकरण तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना था। संस्थान द्वारा संचालित फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम को फसल उत्पादन, उद्यानिकी, पशुधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, उद्यम विकास तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) से संबंधित छह विषयगत मॉड्यूल के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। सहभागी दृष्टिकोण पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के प्रभावी एकीकरण, खेत स्तर पर तकनीकों के सत्यापन, किसानों से प्राप्त सुझावों के आधार पर उनमें सुधार, संस्थागत सहभागिता तथा प्रभावी ज्ञान प्रसार के माध्यम से किसानङ्कवैज्ञानिक सहयोग को सुदृढ़ करना है। कार्यक्रम का लक्ष्य कृषि उत्पादकता, लाभप्रदता और किसानों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

डबल इंजन सरकार के संकल्प को नई गति

केंद्र के ऐतिहासिक निर्णयों से छत्तीसगढ़ को मिलेगा विकास का नया आधार

- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल का जताया आभार
- सेमिकॉन 2.0, राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 और मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना से निवेश, रोजगार और तकनीकी आत्मनिर्भरता को मिलेगा बल

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सेमिकॉन 2.0, राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 तथा मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजनाको स्वीकृति दिए जाने का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज आत्मनिर्भरता, नवाचार और अत्याधुनिक विनिर्माण के नए युग की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्र सरकार के ये तीनों महत्वपूर्ण निर्णय देश की औद्योगिक क्षमता, कृषि सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले सिद्ध होंगे। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि 1,27,500 करोड़ की सेमिकॉन 2.0 योजना देश में सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए विश्वस्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि

छत्तीसगढ़ भी नई औद्योगिक नीति, बेहतर अधोसंरचना, निवेश अनुकूल वातावरण और कौशल विकास के माध्यम से उच्च तकनीक आधारित उद्योगों के लिए तेजी से उभरता हुआ गंतव्य बन रहा है। इस प्रकार की राष्ट्रीय पहल से राज्य में भी निवेश और रोजगार की नई संभावनाएं विकसित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 देश में उर्वरकों की उपलब्धता को सुदृढ़ करेगी तथा किसानों को समय पर आवश्यक उर्वरक उपलब्ध कराने में सहायक होगी। इसका लाभ छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को मिलेगा और कृषि उत्पादन को नई मजबूती प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि और कृषि क्षेत्र की आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ?62,500 करोड़ की मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और निर्यात के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे भारतीय ब्रांडों, अनुसंधान एवं विकास, नवाचार तथा स्थानीय विनिर्माण को व्यापक प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी औद्योगिक निवेश, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी तथा उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिए जा रहे ऐसे दूरदर्शी निर्णय विकसित भारत के साथ-साथ विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को भी नई गति प्रदान करेंगे। नवाचार, निवेश, तकनीकी आत्मनिर्भरता, आधुनिक विनिर्माण और कृषि सशक्तिकरण पर आधारित यह विकास मॉडल आने वाले वर्षों में देश और प्रदेश दोनों की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रही है-विजयशंकर

- भाजपा प्रवक्ता का सवाल: क्या कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के साथ मिली हुई है

रायपुर। संवाददाता

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर दो टूक कहा है कि जो भी कांग्रेस नेता इस भ्रष्टाचार में शामिल या हिस्सेदार हैं, वे स्वयं होकर अपना अपराध स्वीकार कर लें तो यह प्रदेश व जनता के हित के नजरिए से श्रेयस्कर होगा अन्यथा पुलिस तो अपना काम कर ही रही है और पुलिस अपना सब काम बिल्कुल पूरे साक्ष्यों के साथ कर रही है, कहीं पर भी लुका-छिपी जैसा कुछ भी नहीं है। डॉ. मिश्रा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि पूछताछ में तो अग्रवाल खुद ही बता देंगे कि कौन-कौन मिल-बाँटकर पैसा लेते थे, खाते थे और पैसा आता था। आरोपी अग्रवाल के मामले में अब न्यायालय निर्णय करेगा कि इनको कितनी सजा देनी है और क्या करना है? यह न्यायालय का काम है, लेकिन जनता का पैसा यूँ ही कोई लूटकर ले जाए, तो सरकार उसको छोड़ेगी नहीं।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने शुक्रवार को यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह गम्भीर और महत्वपूर्ण मामला है। सन् 2023 तक जब प्रदेश में कांग्रेस की भूपेश

सरकार थी, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल द्वारा जिस तरह लेवी का पैसा, राइस मिलर्स के कस्टम मिलिंग का पैसा, शराब का पैसा पकड़ा गया जो बेनामी तरीके से सूर्यकांत तिवारी की मिली डायरियों में रिकॉर्ड रहा। इन डायरियों में यह भी दर्ज है कि भ्रष्टाचार का पैसा कैसे आया और किसे कितना रुपया दिया गया? इन तथ्यों के प्रकाश में आने के बाद कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के जरिए यह भी खुलासा हुआ है कि पैसा किस माध्यम से कैसे-कैसे आया? इस मामले में पुलिस लगातार अग्रवाल की खोज कर रही थी और अग्रवाल 3 साल भागते रहे और अंतिम में दबाव में जाकर अपनी गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी देने के बाद पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने इस मामले में कांग्रेस की राजनीतिक दुविधा पर करारा कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की ऐसी दशा है कि जिस रामगोपाल अग्रवाल को कल तक वह अपना कोषाध्यक्ष बताती नहीं थक रही थी, दो दिन के अंदर परसों गिरफ्तारी होते ही कांग्रेस के नेता अब यह कह रहे हैं कि यह हमारे कोषाध्यक्ष नहीं है।

गांव में रोजगार, घर में खुशहाली से बदल रही ग्रामीणों की जिंदगी

- वीबी-जी रामजी योजना से 125 दिनों का रोजगार और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी से मजबूत हो रही ग्रामीणों की आजीविका

रायपुर/ संवाददाता

विकसित भारत-गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी रामजी) ग्रामीण परिवारों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरा है। इस योजना के तहत अब सुकमा जिले के ग्रामीणों को अपने ही गांव में 125 दिनों तक रोजगार और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिल रही है। इससे न केवल उनकी आय बढ़ी है, बल्कि पलायन की मजबूरी भी कम हुई है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व छत्तीसगढ में संचालित वीबी-जी रामजी योजना 125 दिनों का रोजगार और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी दी जा रही है। पहले रोजगार की कमी के कारण ग्रामीणों को काम की तलाश में दूसरे शहरों और राज्यों में जाना पड़ता था। अब गांव में ही लगातार काम मिलने से परिवार के साथ रहकर आजीविका चलाना आसान हो गया है। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ सामाजिक जीवन भी बेहतर हुआ है। ग्राम पंचायत गादीरास के शासकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्य से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है, वहीं विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने में भी सुविधा हो रही है। विद्यालय के शिक्षक श्री बसंत शर्मा बताते हैं कि पहले बरसात में स्कूल परिसर में कीचड़ होने से बच्चों को काफी परेशानी होती थी। अब पक्की सड़क बनने से बच्चे आसानी और सुरक्षित तरीके से स्कूल पहुंच रहे हैं। योजना से लाभान्वित श्रमिक श्री रवि पेद्दी कहते हैं कि पहले रोजगार के दिन कम होने से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल था। अब 125 दिनों तक काम और 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलने से घर की जरूरतें आसानी से पूरी हो रही हैं और कुछ बचत भी हो रही है। वहीं श्री अरविंद पेद्दी बताते हैं कि अब गांव में ही रोजगार मिलने से उन्हें रोजी-रोटी के लिए बाहर पलायन नहीं करना पड़ता। इससे वे अपने परिवार के साथ रहकर काम कर पा रहे हैं।

सीएम हेल्पलाइन 1076 बनी आमजन की भरोसेमंद साथी

चार महीने से लंबित मजदूरी का भुगतान शिकायत के 24 घंटे के भीतर हुआ जारी

रायपुर/ संवाददाता

सीएम हेल्पलाइन 1076 यह सुनिश्चित करती है कि छत्तीसगढ़ राज्य के आम नागरिकों की प्रत्येक शिकायत का त्वरित, पारदर्शी एवं जवाबदेही के साथ निराकरण किया जाए। छत्तीसगढ़ सरकार की सीएम हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान का भरोसेमंद माध्यम बनकर उभर रही है। हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों की शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे शासन के प्रति आमजन का विश्वास लगातार मजबूत हो रहा है। बालोद जिले के गुण्डरदेही विकासखंड के ग्राम बेलौदी के एक श्रमिक को

इसका प्रत्यक्ष लाभ मिला, जहां चार माह से लंबित मजदूरी का भुगतान शिकायत दर्ज होने के मात्र 24 घंटे के भीतर कर दिया गया। ग्राम बेलौदी के स्वास्थ्य केंद्र में मजदूरी दर पर कार्यरत भृत्य श्री छत्रपाल साहू को पिछले चार महीनों से मजदूरी का भुगतान नहीं मिला था। लगातार भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने स्थानीय स्तर पर भी अपनी समस्या के समाधान के प्रयास किए, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। इसी दौरान श्री छत्रपाल साहू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार की सीएम हेल्पलाइन 1076 की जानकारी मिली। उन्होंने तत्काल हेल्पलाइन पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होते ही संबंधित विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की। विभागीय कार्रवाई के परिणामस्वरूप शिकायत दर्ज होने के मात्र 24 घंटे के भीतर श्री छत्रपाल साहू के बैंक खाते में चार माह की लंबित मजदूरी की पूरी राशि अंतरित कर दी गई।

भाटापारा में युवती से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। भाटापारा ग्रामीण थाना पुलिस ने युवती से छेड़छाड़, गाली-गलौज और मारपीट के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक ओ.पी. शर्मा के निर्देशन में महिला संबंधी अपराधों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यह कार्रवाई की गई। पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, 6 जुलाई 2026 की शाम आरोपी लक्ष्मीनारायण यदु उर्फ बगल यदु (21 वर्ष), निवासी ग्राम सिंगारपुर उसके घर के सामने आकर अश्लील गाली-गलौज करने लगा।

ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

मुख्यमंत्री साय ने मोबाइल लैब की तकनीकी सुविधाओं का किया अवलोकन

- ग्रामीण विद्यार्थियों तक पहुँचेगी एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन, 3डी प्रिंटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की शिक्षा
- एक वर्ष में 5,000 से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा व्यावहारिक प्रशिक्षण: विज्ञान और नवाचार को मिलेगी नई उड़ान

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने और विज्ञान आधारित शिक्षा को नई दिशा देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने आज विधानसभा परिसर से 'भावना दीदी की साइंस पाठशाला' के अंतर्गत संचालित नि:शुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अत्याधुनिक मोबाइल लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों तक पहुँचकर विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (द्ब), रोबोटिक्स, ड्रोन, 3डी प्रिंटिंग, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (द्बश्वञ्ज), एयरोमॉडलिंग तथा ऑगमेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी (ऋङ्कक्र) जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी आधुनिक विज्ञान और तकनीक की मुख्यधारा से जुड़ें। उन्होंने कहा कि 'भावना दीदी की साइंस पाठशाला' केवल एक मोबाइल लैब नहीं, बल्कि ग्रामीण विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान देने वाली अभिनव पहल है। यह बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार, आत्मविश्वास और तकनीकी दक्षता विकसित करने का प्रभावी माध्यम बनेगी। मुख्यमंत्री श्री साय

ने कहा कि आज पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा साइंस और डिजिटल तकनीकों की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को भी इन उभरती हुई तकनीकों का ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि अवसरों में किसी प्रकार की असमानता न रहे और गाँव का बच्चा भी भविष्य की तकनीकों में उतना ही सक्षम बने जितना किसी महानगर का विद्यार्थी होता है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य भी विद्यार्थियों में कौशल, नवाचार, प्रयोगधर्मिता और रचनात्मक सोच का विकास करना है। यह मोबाइल लैब उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है, जो बच्चों को केवल तकनीक का उपयोग करना ही नहीं सिखाएगी, बल्कि उन्हें नई तकनीकों के निर्माण और नवाचार की दिशा में भी प्रेरित करेगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आज का युग विज्ञान और तकनीक का युग है तथा बच्चों को समय के साथ नई तकनीकों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 'भावना दीदी की साइंस पाठशाला' जैसी अभिनव पहल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी वही अवसर उपलब्ध कराएगी, जो बड़े शहरों के विद्यार्थियों को मिलते हैं। इससे बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी, नवाचार की सोच विकसित होगी और वे आधुनिक तकनीकों को समझने के साथ उनका व्यावहारिक उपयोग भी सीख सकेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मोबाइल लैब के माध्यम से विद्यार्थी केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि स्वयं ड्रोन उड़ाने, रोबोट संचालित करने, 3डी मॉडल तैयार करने और आधुनिक उपकरणों पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण प्रतिभाओं को नई दिशा देने के साथ-साथ भविष्य के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की मजबूत नींव तैयार करेगी।

सुकमा के छात्र नीट और आईआईटी में बना रहे पहचान, शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से बदल रही जिले की तस्वीर

भव्य शाला प्रवेशोत्सव में बच्चों का हुआ आत्मीय स्वागत

तिलक लगाकर किया स्वागत, छात्राओं को मिली साइकिल, बच्चों को बांटे गए बैग, पुस्तकें और गणवेश

सुकमा। नए शिक्षा सत्र की शुरुआत उत्साह और उमंग के साथ हुई। सुकमा जिले में शबरी ऑडिटोरियम में आयोजित जिलास्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में नवप्रवेशित बच्चों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी ने की। इस अवसर पर शिक्षा को बढ़ावा देने और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सुकमा के सुदूर क्षेत्रों के विद्यार्थी भी अब अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर नीट (हश्वश्वञ्ज) और आईआईटी (ढ्ढञ्ज) जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री रूप सिंह मंडावी ने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आज सुकमा तेजी से बदल रहा है और शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि हर माता-पिता का सपना है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ें और समाज तथा देश की सेवा करें। कार्यक्रम में सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक की 30 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गईं। वहीं प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल बैग, पाठ्यपुस्तकें, गणवेश और आवश्यक स्टेशनरी सामग्री प्रदान की गई, ताकि संसाधनों की कमी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। इस अवसर पर कबाड़ से जुगाड़ विषय पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा देखने को मिली। कलेक्टर सुकमा श्री अमित कुमार ने कहा कि सुकमा के दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थी भी अब अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर नीट (हश्वश्वञ्ज) और आईआईटी (ढ्ढञ्ज) जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निःशुल्क कोचिंग, आधुनिक पुस्तकालय और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। कार्यक्रम के अंत में जिला प्रशासन की ओर से मुख्य अतिथि श्री रूप सिंह मंडावी का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी.आर. मंडावी ने आभार व्यक्त करते हुए जिले में शिक्षा से जुड़ी सभी शासकीय योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंगम्मा सोयम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री महेश कुंजाम, नगर पालिका अध्यक्ष श्री हूंगाराम मरकाम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री मुकुंद ठाकुर, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, अभिभावक तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

गुलाब की खुशबू से महकी किसान विकास कुमार की किस्मत

जगदलपुर। पारंपरिक खेती से अलग हटकर अगर आधुनिक और वैज्ञानिक तौर-तरीकों को अपनाया जाए, तो कृषि क्षेत्र में कितनी बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है, इसका जीता-जागता उदाहरण पेश किया है कालीपुर ग्राम के प्रगतिशील किसान श्री विकास कुमार श्रीवास्तव ने। उन्होंने अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से गुलाब की खेती को मुनाफे का एक शानदार जरिया बना दिया है। विकास कुमार श्रीवास्तव ने अपने 8000 वर्गमीटर के खेत में संरक्षित स्थिति में व्यावसायिक स्तर पर गुलाब की वैज्ञानिक खेती की शुरुआत की थी। सही समय पर सिंचाई, संतुलित पोषण प्रबंधन और उन्नत फसल संरक्षण उपायों के बदौलत उनकी फसल में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादकता देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपने खेत से लगभग एक लाख 60 हजार गुलाब के डंठलों का बंपर उत्पादन प्राप्त किया। बाजार में इन गुलाबों की भारी मांग के चलते विकास कुमार को अपनी फसल का कुल बाजार मूल्य लगभग 8 लाख रुपए प्राप्त हुआ। यदि इस खेती के आर्थिक गणित को समझें, तो इसमें कुल 4 लाख 20 हजार रुपए की लागत आई थी, जिसे निकालने के बाद उन्हें 3 लाख 80 हजार रुपए का सीधा और शुद्ध मुनाफा हासिल हुआ। यह उपलब्धि साबित करती है कि कम क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर उद्यानीकी फसलों से अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। गुलाब की इस सफल खेती ने न केवल विकास कुमार श्रीवास्तव को आत्मनिर्भर बनाया है, बल्कि आज वे आस-पास के क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी एक बड़े प्रेरणास्त्रोत और रोल मॉडल बन चुके हैं।

नव पदस्थ सीईओ श्री एम. भार्गव ने बस्तर मुन्ने शिविर का किया निरीक्षण

दंतेवाड़ा। जिले के नव पदस्थ जिला पंचायत सीईओ श्री एम. भार्गव ने ग्राम पंचायत मेटापाल क्रमांक-2 में आयोजित बस्तर मुन्ने शिविर का निरीक्षण कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया, ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा सेवा वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। सीईओ श्री भार्गव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि बस्तर मुन्ने शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को एक ही स्थान पर विभिन्न शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने आधार कार्ड निर्माण एवं संशोधन, आयुष्मान कार्ड पंजीयन, श्रम कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी), जाति प्रमाण पत्र तथा महतारी वंदन योजना सहित विभिन्न सेवाओं में तेजी लाने और पात्र हितग्राहियों को बिना विलंब लाभ पहुंचाने को कहा।

वन विभाग की पहल से आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिला स्वरोजगार का सहारा

17 लाख रुपये के ऋण से चार हितग्राहियों को मिला नया जीवन

बीजापुर। वन प्रबंधन समितियों के खातों में जमा लाभांश एवं चक्रीय निधि की राशि का उपयोग करते हुए वनमंडल बीजापुर ने आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं वनांचल के ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल की है। विभाग द्वारा कुल 17 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराकर चार हितग्राहियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत पामेड़ एवं आवापल्ली परिक्षेत्र के चार हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। इनमें तीन हितग्राहियों को किराना दुकान संचालन हेतु क्रमशः 2 लाख, 3 लाख एवं 2 लाख रुपये तथा एक हितग्राही को ट्रैक्टर, ट्रॉली एवं डोजर खरीदने के लिए 10 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। लाभान्वित हितग्राहियों में दिलीप बीराबोईन (कोतापल्ली समिति), दिनेश कुमार कचलम (मुरदोंडा समिति), श्रीमती जोशिला भगत (कोतापल्ली समिति) तथा नागुल सत्यनारायण (आवापल्ली समिति) शामिल हैं। इन सभी को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता से वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे। वन विभाग का उद्देश्य केवल वन संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि वनांचल के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान को भी बढ़ावा देना है। यह पहल विशेष रूप से आत्मसमर्पित नक्सलियों को सम्मानजनक आजीविका उपलब्ध कराकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, समाज में स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करने तथा क्षेत्र में शांति, विश्वास और समावेशी विकास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वनमंडल बीजापुर ने भविष्य में भी पात्र हितग्राहियों को विभिन्न आजीविका आधारित योजनाओं से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की बात कही है। यह पहल वनांचल के ग्रामीणों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास एवं आर्थिक सशक्तिकरण का प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभरी है।

ऑनलाइन आवेदन करने के कुछ घंटों में जुड़ा राशन कार्ड में आवेदक की पुत्री का नाम

सेवा सेतु पोर्टल के जरिए एक ही दिन में हुआ निराकरण

कलेक्टर ने बसंत को सौंपा संशोधित राशन कार्ड

कांकेर। छत्तीसगढ़ शासन की जनहितकारी पहल सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और सुलभ सेवाएं प्रदाय कराई जा रही हैं। इसी क्रम में ग्राम तेलावट निवासी बसंत कुमार साहू ने अपनी तीन वर्षीय बेटी गेश्रीका का नाम राशन कार्ड में जोड़ने के लिए सेवा सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन के अगले ही दिन उनकी बेटी का नाम राशन कार्ड में जोड़ दिया गया। राशन कार्ड की अद्यतन प्रति जिला कलेक्टर निलेश महादेव क्षीरसागर ने आवेदक साहू को अपने हाथों से प्रदान की। त्वरित कार्रवाई से प्रसन्न बसंत कुमार साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से अब सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ते। घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर कम समय में ही आवश्यक सेवाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु पोर्टल से आम नागरिकों का समय और श्रम दोनों की बचत हो रही है तथा शासन की सेवाएं अधिक सरल, सुलभ और पारदर्शी बनी हैं।

विषय विशेषज्ञों का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

उत्तर बस्तर कांकेर । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ अंतर्गत नवनियुक्त विषयवस्तु विशेषज्ञों का ''बदलते परिदृश्य में कृषि विज्ञान केन्द्रों की कार्यप्रणाली'' विषय पर ओरिएंटेशन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 जुलाई तक कृषि विज्ञान केन्द्र कांकेर में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने ऑनलाईन माध्यम से कहा कि विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि अनुसंधान एवं कृषक समुदाय के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। विशेष रूप से बस्तर संभाग में पदस्थ नवनियुक्त विषयवस्तु विशेषज्ञों से समर्पण, नवाचार एवं सेवा भाव के साथ कार्य करते हुए किसानों तक उन्नत कृषि तकनीकों का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करने की बात कही। इसके अलावा डॉ. एस. आर. के. सिंह निदेशक ने कृषि विज्ञान केन्द्रों, राज्य कृषि विभाग एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए डिजिटल एवं ई-एक्सटेंशन माध्यमों के प्रभावी उपयोग की महत्ता बताई। कृषि विज्ञान केन्द्र के डॉ. बीरबल साहू ने बताया कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के 27 कृषि विज्ञान केन्द्रों के कुल 33 विषय विशेषज्ञ सम्मिलित हुए।

राष्ट्रीय अजजा आयोग के विधिक सलाहकार ने वन-धन केन्द्र इच्छापुर का किया अवलोकन

उत्तर बस्तर कांकेर। भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली के वरिष्ठ विधिक सलाहकार प्रकाश कुमार उईके आज जिले के प्रवास के दौरान कांकेर विकासखंड के ग्राम इच्छापुर पहुंचे जहां उन्होंने वन-धन केन्द्र का अवलोकन कर समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने हर्रा प्रसंस्करण केन्द्र (प्रोसेसिंग यूनिट) में समूह की महिलाओं से चर्चा की तथा इससे होने वाली आय के बारे मे पूछा। साथ ही और भी बेहतर ढंग से कार्य करने की बात कहीं। इस अवसर पर उनके द्वारा प्रसंस्करण केन्द्र परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत पौधे भी रोपे गए। इस मौके पर उनके साथ आए अजय कुमार चौबे, कुंवर जितेन्द्र सिंह राणा तथा सूर्यनारायण सूरी तथा डीएफओ कांकेर रौनक गोयल व वन विभाग का अमला मौजूद था।

18 जुलाई तक जिले में चलेगा विशेष एचपीवी टीकाकरण अभियान

14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क लगाई जाएगी एचपीवी वैक्सीन

दंतेवाड़ा। जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय रामटेके के निर्देशानुसार 18 जुलाई तक विशेष एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले की 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की उन किशोरी बालिकाओं को निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन लगाई जाएगी, जिन्होंने अपना 14वां जन्मदिन पूरा कर लिया है, लेकिन अभी 15वां जन्मदिन नहीं मनाया है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. एस. मंडल ने बताया कि एचपीवी संक्रमण गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर का प्रमुख कारण माना जाता है। समय पर एचपीवी टीकाकरण कराने से भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और विश्वभर में करोड़ों लोगों को सफलतापूर्वक लगाई जा चुकी है। उन्होंने जिले के पात्र किशोरियों एवं उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे इस विशेष अभियान का लाभ उठाते हुए समय पर टीकाकरण अवश्य कराएं।

पिपलावंड मारीपारा का आंगनबाड़ी केंद्र बना गुणवत्ता, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण

बस्तर में प्रारंभिक शिक्षा का नया मॉडल : आंगनबाड़ी बनी बच्चों के सपनों की पाठशाला

बस्तर। छत्तीसगढ़ में प्रारंभिक बाल शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में बस्तर जिले के ग्राम पंचायत पिपलावंड के मारीपारा आंगनबाड़ी केंद्र ने एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मनरेगा और विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से निर्मित यह आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र अब केवल बच्चों के पोषण और देखभाल का केंद्र नहीं, बल्कि आकर्षक, सुरक्षित और नवाचार आधारित प्रारंभिक शिक्षा का सशक्त माध्यम बन गया है। पहले जर्जर भवन में संचालित होने वाले इस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पढ़ाई और गतिविधियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ग्राम पंचायत की पहल पर जनपद पंचायत बस्तर के माध्यम से नवीन भवन की स्वीकृति प्राप्त की गई। वर्ष 2024-25 में कुल 11.69 लाख रुपये की लागत से भवन का निर्माण कराया गया, जिसमें मनरेगा से 8 लाख रुपये, महिला एवं बाल विकास विभाग से 2 लाख रुपये तथा गौड़ खनिज मद से 1.69 लाख रुपये की राशि का उपयोग किया गया। नवीन भवन का बाहरी स्वरूप बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। भवन की दीवारों पर हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी अक्षर, आकर्षक चित्र, अल्फाबेट ट्री और शैक्षणिक भित्ति चित्र उकेरे गए हैं, जिससे बच्चों में खेल-खेल में सीखने की रुचि विकसित हो रही है। आंगनबाड़ी के अंदर भी सीखने के अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। सचित्र हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी अल्फाबेट, 1 से 100 तक की संख्या तालिका, बच्चों की लंबाई मापने के लिए विशेष ग्रोथ ट्री सहित कई इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में केंद्र में 22 बच्चे पंजीकृत हैं, जो प्रतिदिन उत्साहपूर्वक शिक्षा एवं पोषण सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। यह आंगनबाड़ी केंद्र सामुदायिक सहभागिता का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान कर रही हैं और स्थानीय समुदाय भी केंद्र के संचालन एवं रखरखाव में सक्रिय सहयोग दे रहे हैं।

जिला स्तरीय जन्म-मृत्यु अंतरविभागीय समन्वय की हुई बैठक, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के दिशा निर्देशों के बारे में कराया गया अवगत

दंतेवाड़ा । विगत दिवस जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय जन्म-मृत्यु अंतरविभागीय समन्वय की बैठक आयोजित किया गया था। बैठक में जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा जन्म -मृत्यु पंजीयन के दिशा निर्देश के विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 27 जनवरी 2026 अधिसूचना के तहत ऐसी घटना जो 22 दिन से 30 दिन के भीतर के घटना की पंजीयन रजिस्ट्रार द्वारा की जाए तो 20 रूपये के विलंब फीस के भुगतान पर पंजीयन किया जायेगा। इसके अलावा ऐसी घटना जो 30 दिन से 1 वर्ष के भीतर घटना के पंजीयन की जानकारी रजिस्ट्रार को दी जाये तो 100 रुपये के विलंब फीस के भुगतान तथा 1 वर्ष के पश्चात् घटना के पंजीयन, के लिए 100 रूपये के विलंब फीस का प्रावधान है। इसके साथ ही एक वर्ष पश्चात् रिकार्ड की खोज बीन हेतु प्रत्येक वर्ष का 20 रुपये का शुल्क लिया जावेंगा। प्रमाण पत्र गुम हो जाने की स्थिति में द्वितीय प्रति जारी करने पर 50 रुपये का शुल्क लिया जावेगा। पूर्व में पंजीकृत जन्म, मृत्यु के मामले में जन्म, मृत्यु, नाम तिथि एवं स्थान में संशोधन नहीं किया जा सकता। जन्म के मामले में नाम (बच्चे, माता, पिता) संशोधन किया जा सकता है केवल विशेष परिस्थितियों जैसे लिपिकीय त्रुटि होने पर, जन्म के पश्चात् 5 वर्ष की आयु तक साक्ष्य (शाला प्रवेश आधार कार्ड, अन्य शासकीय दस्तावेज) के आधार पर किया जा सकता है। इसके अलावा मृत्यु के मामले में नाम (मृतक, माता, पिता) संशोधन नहीं किया जा सकता है परन्तु केवल लिपिकीय त्रुटि होने पर तथा मृत्यु पंजीयन के पूर्व शासकीय अभिलेख जिसमे सही नाम हो प्रस्तुत करने पर (प्रस्तुत अभिलेख में कांट-छांट मान्य नही किया जायेगा) किया जा सकता है। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(2) एवं धारा 13 (3) अधिनियम के तहत लेने वाले दस्तावेजों के तहत आवेदन, शपथ पत्र, नोटरी, पंचनामा घटना के संबंध में, घटना की परिशुद्धता प्रमाण पत्र, जच्चा-बच्चा कार्ड, स्व परीक्षण परीक्षण रिपोर्ट, आधार कार्ड-जन्म प्रकरण मे माता-पिता का मृत्यु में मृतक का, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, शासकीय सेवक होने की स्थिति में सेवा पुस्तिका, शासकीय अभिलेख आवश्यक होगें। इसके साथ ही चलित वाहन, 108 एम्बुलेंस में मृत्यु के प्रकरण के अंतर्गत मृत्यु एक ही शहर, कस्बे या गावं के भीतर सचल वाहन या एम्बुलेंस में हुई हो अथवा सार्वजनिक निवास जैसे-ट्रेन, विमान, बस आदि में लंबी दूरी की यात्रा में मृत्यु हुई यानि मृतक स्थान के अधिकार क्षेत्र के बाहर या अन्य राज्य में हुई हो।

वृहद वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने तैयारियां सुनिश्चित करें : दिव्या मिश्रा

सभी वर्गों की सहभागिता से पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अधिक से अधिक पौधरोपण कराने के दिए निर्देश

बालोद। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले के सभी विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को बालोद जिले में वृहद वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने हेतु सभी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में उक्ताशय के निर्देश दिए हैं। दिव्या मिश्रा ने कहा कि वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों की सहभागिता से अधिक से अधिक पौधरोपण कर पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य में जिले वासियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित कराने को कहा। बैठक में वन मण्डलाधिकारी अभिषेक अग्रवाल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी, अपर चंद्रकांत कौशिक एवं अजय किशोर लकरा, संयुक्त कलेक्टर मधुहर्ष सहित राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

पौध रोपण की अनिवार्य रूप से जानकारी देने के निर्देश

बैठक में कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन अंकुर अभियान के तहत जिले में एक ही दिन में 1 लाख 91 हजार सीड बॉल के रोपण के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जिले में यह महत्वपूर्ण कार्य समाज के सभी वर्गों के साथ-साथ जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों के सक्रिय सहभागिता के फलस्वरूप संपन्न हुआ है। उन्होंने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के अलावा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को पिछले वर्ष वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत रोपे गए पौधों की पूरी जानकारी देने के भी निर्देश दिए। इसके अंतर्गत उन्होंने पौधों की सर्वाइवल रिपोर्ट एवं अन्य सभी जानकारियां प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने इस वर्ष वृहद वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक पौधों के रोपण हेतु आवश्यक स्थानों की जानकारी देने को कहा। इसके अलावा उन्होंने विकासखण्डवार पौध रोपण की भी अनिवार्य रूप से जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

किसानों को किसी भी स्थिति में खाद, बीज की नही होनी चाहिए कोई कठिनाई

बैठक में उन्होंने जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों के सुबह 10 बजे बायोमेट्रिक उपस्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को सुबह 10 बजे अनिवार्य रूप से अपने कार्य स्थल पर पहुँच कर अपना बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व एवं वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाले वन भूमि के सर्वेक्षण कार्य के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य को निर्धारित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से सुष्घर छत्तीसगढ़ अभियान के कार्य योजना के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने जिले में इस अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न करने बेहतर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में दिव्या मिश्रा ने कृषि, सहकारिता एवं अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को जिले में खाद, बीज की समुचित उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले के किसानों को किसी भी स्थिति में खाद, बीज की प्रबंध करने कोई कठिनाई नही होनी चाहिए।

सर्वाइकल कैंसर के बचाव हेतु टीकाकरण के कार्य की समीक्षा

इसके अलावा उन्होंने एग्रीस्टेक पोर्टल में किसान पंजीयन के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने इस कार्य को विशेष प्राथमिकता के साथ पूरा करते हुए निर्धारित समयावधि में जिले के शत प्रतिशत कृषकों का एग्रीस्टेक पोर्टल में अनिवार्य रूप से पंजीयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव सुनिश्चित करने हेतु 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के बचाव हेतु टीकाकरण के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी को इस कार्य हेतु शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम की तैनातगी सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने पालक समिति बैठक आयोजित कर बच्चों के पालकों एवं अभिभावकों को इसके संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान करने के भी निर्देश दिए।

सुपेला भिलाई पशु चिकित्सालय के जर्जर भवन पर विधायक सेन ने किया सवाल

भिलाई नगर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चतुर्थ दिवस वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने सुपेला भिलाई स्थित पशु चिकित्सालय के जर्जर भवन का मामला प्रमुखता से उठाया। उन्होंने ध्यानाकर्षण के जरिए इस अहम विषय पर सरकार से सीधे सवाल किए।

विधायक ने पूछा कि क्या अत्यंत क्षतिग्रस्त हो चुके इस भवन के जीर्णोद्धार या नवीन निर्माण की कोई योजना है? उन्होंने अस्पताल में ऑपरेशन रूम, डॉक्टर रूम और शल्य चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग भी की। खाली पदों पर पशु चिकित्सा सहायक विशेषज्ञों की तत्काल पदस्थापना का आग्रह किया। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने सदन में स्थिति स्पष्ट करते हुए स्वीकार किया कि उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला दुर्ग द्वारा नवीन भवन निर्माण का प्रस्ताव मिला है। 10 अप्रैल 2026 को प्राप्त यह प्रस्ताव वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। हालांकि, विभागीय मंत्री ने नए संसाधनों और पदों की वृद्धि के संबंध में कोई भी निश्चित समय-सीमा बताने में असमर्थता जताई।

अपनी बेटी प्रिया के जन्मदिन पर सरिता अनमोल जैन ने रानो में कराया नेवता भोज

99 बच्चों को किया जूते एवं मोजे का वितरण

बेमेतरा। साजा विकास खण्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रानो में थान खम्हरिया निवासी सरिता अनमोल जैन ने दुर्ग निवासी अपनी बेटी प्रिया प्रेरक चोपड़ा के जन्मदिन के अवसर पर पूर्व माध्यमिक विभाग के पूरे 99 बच्चों को जूते एवं मोजे का वितरण किया। सभी बच्चों एवं स्टॉफ ने उनकी बेटी को वीडियो कॉल के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनायें प्रेषित की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे नेवता भोज में प्राथमिक एवं माध्यमिक के सभी बच्चों को पूड़ी, सब्जी एवं जलेबी दिया। बच्चों को मध्याह्न भोजन में दाल चाँवल दिया गया। नवाचारी शिक्षिका प्रतीक जैन ने बताया कि यह सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामुदायिक भागीदारी पहल है। इसके माध्यम से कोई भी आम नागरिक, समुदाय या संगठन अपने खास मौके जैसे जन्मदिन या सालगिरह आदि में सरकारी शालाओं एवं आंगनबाड़ियों में बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है। इससे बच्चों को अतिरिक्त पोषण भी मिलता है, समानता की भावना विकसित होती है तथा सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत समुदाय एवं शाला के बीच अपनेपन की भावना में वृद्धि होती है।सभी बच्चों के चेहरे उपहार पाकर खुशियों से खिल उठे। उन्होंने सरिता अनमोल जैन को धन्यवाद कहा। सरिता जी इससे पहले भी शाला में कॉपी, पेन, कलर पेन्सिल एवं बिस्किट वितरित कर चुकी हैं। आज का उनका ये आयोजन निश्चित रूप से शाला के लिए बहुत बड़ा योगदान है। नवाचारी शिक्षिका प्रतीक जैन ने इस आयोजन के लिए पूर्व ही तैयारी कर सभी बच्चों के जूतों के नंबर उन्हें उपलब्ध कराया ताकि आसानी से बच्चों को चीजें उपलब्ध हो सके। उन्होंने सरिता जैन को बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। जिन्होंने इस कार्य के लिए 35000 रुपए की राशि खर्च की है। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य द्वारिका राम वर्मा, माध्यमिक प्रधान पाठक किशुन राम साहू, प्राथमिक प्रधान पाठक उत्तम साहू, कनकलता सरसुधे, अवधराम वर्मा, प्रतीक जैन, दीनदयाल वर्मा, प्रज्ञा जैन, अमृत गुप्ता, सभी रसोईया बहनें एवं बच्चे उपस्थित रहे।

सिटी प्रेस क्लब ने पूर्व एसपी को दी भावभीनी विदाई, नवागत एसपी का अभिनंदन

मीडिया और पुलिस की साझेदारी से अपराध नियंत्रण होगा, जनता का विश्वास सर्वोच्च प्राथमिकता : एस पी बंसल

बेमेतरा। सिटी प्रेस क्लब की ओर से पूर्व पुलिस अधीक्षक एवं वर्तमान डीआईजी रामकृष्ण साहू को भावभीनी विदाई तथा नवागत पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के सम्मान में गरिमामय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पत्रकारों और पुलिस अधिकारियों ने जिले में बेहतर पुलिसिंग, पारदर्शिता और मीडिया-पुलिस समन्वय को लेकर अपने विचार साझा किए। समारोह में सदस्य दिनेश दुबे एवं वक्ताओं ने पूर्व एसपी रामकृष्ण साहू के करीब दो वर्ष छह माह के कार्यकाल को जिले के सबसे लंबे और उल्लेखनीय कार्यकालों में से एक बताते हुए उनकी कार्यशैली, संवेदनशीलता और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों की सराहना की। पत्रकारों ने कहा कि उनके कार्यकाल में पुलिस और मीडिया के बीच सकारात्मक संवाद स्थापित हुआ, जिससे कई मामलों में अपराध नियंत्रण और जनजागरूकता को मजबूती मिली। पत्रकार दिनेश दत्त दुबे, योगेश राजपूत, आनंद साहू, अरुण सोनी, अनीश मेमन खिलेश धृतलहरे एवं ममता ग्वालवंशी,आशीष कांटले, अरविंद गोस्वामी ने भी साहू के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अमीन पप्पू रवानी ने नवागत पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल का स्वागत करते हुए कहा कि जिले को उनके अनुभव और ऊर्जा का लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस और मीडिया के बीच समन्वय की परंपरा आगे भी मजबूत होगी तथा जनहित से जुड़े मुददों पर सकारात्मक सहयोग जारी रहेगा।

मीडिया के सहयोग से होगी बेहतर पुलिसिंग : त्रिलोक बंसल

अपने संबोधन में नवागत पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का सशक्त स्तंभ है और समाज तथा प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण, यातायात व्यवस्था, साइबर अपराधों की रोकथाम और जनजागरूकता जैसे विषयों पर पुलिस को मीडिया का सकारात्मक सहयोग हमेशा मिलता रहा है। उन्होंने कहा, मेरी प्राथमिकता आम नागरिकों की सुरक्षा, त्वरित कार्रवाई और पारदर्शी पुलिस व्यवस्था रहेगी। मीडिया के साथ नियमित संवाद बनाए रखा जाएगा, ताकि सही जानकारी समय पर लोगों तक पहुंचे और समाज में विश्वास का वातावरण मजबूत हो। पुलिस और मीडिया मिलकर जनहित में बेहतर कार्य करेंगे।

मीडिया का सहयोग हमेशा याद रहेगा : रामकृष्ण साहू

पूर्व पुलिस अधीक्षक एवं वर्तमान डीआईजी रामकृष्ण साहू ने कहा कि बेमेतरा में मिले सहयोग को वे हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि अपने पूरे कार्यकाल में उनका प्रयास सकारात्मक सोच के साथ पुलिस और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने का रहा। अपराधों की रोकथाम, जनजागरूकता और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में मीडिया ने हमेशा रचनात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि स्थानांतरण के बाद भी उनका आत्मीय रिश्ता बेमेतरा और यहां के पत्रकारों से बना रहेगा। आयोजन के लिए उन्होंने सिटी प्रेस क्लब का आभार व्यक्त किया। समारोह में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश यादव, यातायात प्रभारी खलको, थाना प्रभारी सोनल ग्वाला सहित पुलिस विभाग के अधिकारी एवं सिटी प्रेस क्लब के सदस्य मेडी धीवर, आकाश रोहरा,दीपेश राजपूत, अजीत राजपूत, अमित, भरत, ताम्रध्वज साहू सहित अन्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में पूर्व एसपी रामकृष्ण साहू को स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानपूर्वक विदाई दी गई तथा नवागत एसपी त्रिलोक बंसल का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया गया।

जिले के विधायक महीने में एक दिन सिर्फ महिलाओं के लिए निकाले : प्रज्ञा निर्वाणी

बेमेतरा। महिलाओं की समस्याओं के समाधान को लेकर भाजपा महिला मोर्चा बेमेतरा ने ऐसी पहल की है, जो सफल होने पर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए जनसेवा का नया मॉडल बन सकती है, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रज्ञा निर्वाणी ने जिले के सभी विधायकों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि प्रत्येक माह एक दिन केवल महिलाओं के लिए समर्पित किया जाए, जिसमें विधायक अपनी-अपनी विधानसभा में आयोजित महिला जनसुनवाई एवं समाधान दिवस में स्वयं उपस्थित होकर महिलाओं की समस्याएं सुनें और उनके त्वरित निराकरण की प्रक्रिया शुरू कराएं। प्रज्ञा निर्वाणी ने अपने पत्र में कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब समाज के सबसे संवेदनशील वर्ग की आवाज सीधे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, यदि हर विधायक महीने में केवल एक दिन महिलाओं को समर्पित कर दे, तो हजारों बहनों को अपनी समस्याएं रखने, समाधान पाने और शासन-प्रशासन पर विश्वास मजबूत करने का अवसर मिलेगा। प्रस्ताव के अनुसार यह जन सुनवाई प्रत्येक माह विधानसभा के अ ल ग - अ ल ग मंडलों में आयोजित की जाएगी, ताकि दूरस्थ गांवों की महिलाओं को भी अपने क्षेत्र में ही जनप्रतिनिधियों से मिलने का अवसर मिल सके, कार्यक्रम का संचालन भाजपा महिला मोर्चा करेगा तथा प्राप्त आवेदनों के निराकरण की नियमित समीक्षा भी की जाएगी।

प्रज्ञा निर्वाणी ने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान केवल नारों से नहीं, बल्कि उसकी समस्याओं के समाधान से होता है,यही वास्तविक अर्थों में नारी वंदन और नारी सशक्तिकरण है, महिलाओं का मनोबल बढ़ाना, उन्हें न्याय दिलाना और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना ही इस अभियान का मूल उददेश्य है।

इस जनसुनवाई अभियान में भाजपा महिला मोर्चा की जिला, मंडल एवं बूथ स्तर की पदाधिकारी सक्रिय भूमिका निभाएंगी, साथ ही संबंधित क्षेत्र के विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य तथा अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे, जिससे अधिकांश समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही सुनिश्चित किया जा सके।

महिला मोर्चा की जिला मंत्री मनीषा शर्मा का मानना है कि यदि यह अभियान बेमेतरा जिले में सफल होता है तो इसे पूरे छत्तीसगढ़ में लागू किया जा सकता है, यह पहल महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा, न्याय और सुशासन से जोड़ने की दिशा में एक प्रभावी कदम होगी तथा जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच विश्वास का नया अध्याय लिखेगी,यह जानकारी जिला महामंत्री मधु राजपूत ने दी।

नपाध्यक्ष ने थोक चिल्लर फल व्यापारियों के साथ शहर से बाहर फल मंडी संचालित करने पर हुई चर्चा

बेमेतरा। नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा की अध्यक्षता में थोक एवं चिल्लर फल व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था, आमजन की सुविधा तथा व्यापारिक गतिविधियों को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से फल दुकानों एवं थोक फल मंडी को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान फ्रूट व्यापारियों से सुझाव और राय ली गई। व्यापारियों ने भी बेहतर व्यवस्था के लिए सहयोग करने का भरोसा दिलाया। इस पहल से शहर में यातायात का दबाव कम होने, बाजार व्यवस्था में सुधार आने तथा व्यापारियों एवं आम नागरिकों को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित वातावरण मिलने की उम्मीद जताई गई। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि व्यापारियों के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए सभी संबंधित पक्षों की सहमति से आगे की कार्यवाही की जाएगी, ताकि शहर के विकास और यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नरेश वर्मा सहित फल व्यापारी मौजूद रहे।

सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुरक्षा उपकरण वितरित

दल्ली राजहरा। नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा में नमस्ते दिवस के अवसर पर नपा अध्यक्ष तोरण लाल साहू की उपस्थिति में सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई में कार्य करने वाले कर्मचारियों का मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण कराया तथा उन्हें सुरक्षा उपकरण प्रदान किया गया। विदित हो कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से जुलाई 2023 में राष्ट्रीय यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थिति की तंत्र कार्य योजना (नमस्ते) की शुरुआत की गई थी, इसके अंतर्गत पूर्व की स्वरोजगार योजना एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगे कर्मचारी, सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इस योजना का उददेश्य सफाई कर्मियों की सुरक्षा, गरिमा सुनिश्चित करना तथा सफाई कार्यों में शून्य मृत्यु दर प्राप्त करना है। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद दल्लीराजहरा के 16 सेप्टिक टैंक सफाई से संबंधित कर्मचारी को सुरक्षा उपकरण प्रदान किया गया। इस अवसर पर पार्षद भूपेंद्र श्रीवास, स्वास्थ्य अधिकारी राम गोपाल चंद्राकर, प्रभारी लेखपाल सुनील तारम, स्टोर प्रभारी पंकज चंद्राकर।

भिलाई निगम में 2,878 नियमितीकरण प्रकरण लंबित, विधानसभा में विधायक रिकेश ने उठाया मुद्दा

सरकार ने माना—हजारों आवेदन प्रक्रियाधीन, दस्तावेजों की कमी और जांच से हो रही देरी

भिलाई नगर। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने विधानसभा मानसून सत्र के चतुर्थ दिवस भिलाई नगर निगम में लंबित नियमितीकरण प्रकरणों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने सरकार से लंबित आवेदनों, देरी के कारणों और प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा पर जवाब मांगा।

विधायक रिकेश सेन ने पूछा कि पिछले तीन वर्षों में नियमितीकरण के कितने आवेदन लंबित हैं। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि फाइलों पर अंतिम निर्णय क्यों नहीं हो रहा। नियमितीकरण प्रक्रिया जारी है या स्थगित कर दी गई है। साथ ही प्रक्रिया पूरी करने की निश्चित समय-सीमा बताने की मांग की।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में लिखित उत्तर प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में 2,878 नियमितीकरण प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं।

सरकार के अनुसार अभिलेखों की जांच में समय लग रहा है। आवश्यक दस्तावेजों की कमी भी प्रमुख कारण है। कई मामलों में स्थल निरीक्षण लंबित है। इन्हीं कारणों से अंतिम निर्णय में देरी हो रही है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि नियमितीकरण प्रक्रिया स्थगित नहीं की गई है। सभी प्रकरण प्रचलित कानून और नियमों के अनुसार निराकृत किए जा रहे हैं। नियमितीकरण प्रकरणों के निराकरण के लिए अलग समय-सीमा निर्धारित नहीं है। सभी मामलों का नियमानुसार और यथाशीघ्र निराकरण किया जा रहा है।

नमस्ते दिवस पर सफाई मित्रों का सम्मान निकाय में स्वच्छता दीदियों को साड़ी वितरण

डोंगरगांव नगर। नगर पालिका परिषद में नमस्ते योजना (नेशनल एक्शन फॉर मेकनाइज़ सेनिटेशन ई कोसिस्टम) अंतर्गत नमस्ते दिवस का आयोजन किया गया। सेप्टिक टैंक सफाई मित्रों का पुष्पमाला एवं शॉल पहनाकर सम्मान किया। वहीं स्वच्छता दीदियों को साड़ी वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अंजू त्रिपाठी ने की। इस अवसर पार्षदगण पुरुषोत्तम साहू, पदमनी ठाकुर, कोमल साहू, निर्मला मालेकर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी विनम्र जेमा सहित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। इस मौके पर अध्यक्ष अंजू त्रिपाठी ने कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों को स्वच्छता शपथ दिलाई। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण जैसे ग्लावस, मास्क, फ्लोसेंट जैकेट के साथ ही कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने शहर की साफ-सफाई में निरंतर सुधार हेतु सभी सफाई कर्मियों को प्रेरित किया। नमस्ते दिवस कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका के सभी कर्मचारियों का मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। यूनिट के माध्यम से कर्मियों की रक्तचाप, शुगर एवं सामान्य स्वास्थ्य जांच की गई।

स्वत्वाधिकारी , प्रकाशक, एवं मुद्रक ज्वाला प्रसाद अग्रवाल द्वारा असमा पब्लिशर्स प्रा. लि. जयस्तंभ चौक, रायपुर, पिन - 492001 छत्तीसगढ़ से मुद्रित एवं झुलेलाल मंदिर के पीछे, पाटनकर कालोनी, सिंधी कालोनी, दुर्ग पिन- 491001 (छ.ग.) से प्रकाशित।
संपादक - ज्वाला प्रसाद अग्रवाल । e mail - jwalaexpress@gmail.com , मोबाईल- 9993590905, 7000489995